राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

'शिक्षा'

1991-92

शिक्षा विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

'शिक्षा'

1991-92

शिक्षा विभाग, राजस्थान

NIEPA DC
D07272

- 544
370.6
RAJ - V
LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7272
Date 16.11.92

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	शिक्षा का विकास : योजना एवं प्रगति	1
2.	प्राथमिक शिक्षा	3
3.	माध्यमिक शिक्षा	8
4.	राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, उदयपुर	12
5.	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर	19
6.	उच्च शिक्षा	23
7.	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	25
8.	अजमेर विश्वविद्याल, अजमेर	27
9.	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्याल, उदयपुर	28
10.	जोधपुर विश्वविद्याल,	29
11.	कोटा खुला विश्वविद्यालय	30
12.	संस्कृत शिक्षा	31
13.	एन. सी. सी. निदेशालय, राज. जयपुर	32
14.	राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड़	35
15.	भाषा विभाग	36
16.	राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर	39
17.	राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर	40
18.	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	40
19.	राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी	42
20.	राजस्थान की उर्दू अकादमी	43
21.	राजस्थान सिन्धी अकादमी	44
22.	राष्ट्रीय सेवा योजना	45
23.	राजस्थान राज्य पाठ्य-पुस्तक मण्डल	46
24.	विद्यालयी शिक्षा महत्वपूर्ण शैक्षिक आंकड़े, 1991-92	48

शिक्षा का विकास : योजना एवं प्रगति

शिक्षा का स्वस्थ्य एवं विकसित स्वरूप राष्ट्रीय विकास का प्रथम सोपान है। सक्षम, निष्ठावान एवं कार्यकुशल नागरिक देश के सर्वाधिक मूल्यवान संसाधन हैं। वे मूल्यवान संसाधन तो है ही साथ ही हमारे सर्म्पूण विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लक्ष्य भी हैं।

राष्ट्र के सम्पूर्ण बचत, उत्पादन, विकास, योजना, आर्थिक गतिविधियों एवं अन्य प्रयासों का समन्वित उद्देश्य नागरिकों को भौतिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि को मजबूत बनाना है। समृद्ध व्यक्तित्व के प्रयास शिशु छात्र से आरम्भ किये जाकर अनवरत जीवन-पर्यन्त चलते हैं। विज्ञान, टैक्नोलोजी, कला-सस्कृति खेल-कूद, व्यवसाय एवं जीवन स्तर को प्रभावित करने वाले समस्त तत्वों का शिक्षा में समुचित समन्वय करना हमारा लक्ष्य रहा है। यही कारण है कि शिक्षा की संरचना तथा शिक्षा के उद्देश्य अत्यधिक व्यापक एवं बहुआयामी हो गये है। स्वाभाविक है कि शैक्षिक प्रगति की दिशा में किये जा रहे हमारे प्रयास भी इतने ही बहुआयामी एवं दूरगामी रहे हैं।

राज्य के शिक्षा विभाग का प्रथम व सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व शिक्षा के उपलब्ध ढांचे को जन-उन्मुख बनाना है व शिक्षा सुविधाओं को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसी दृष्टि से उपेक्षित एवं कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले वर्गों तक आवश्यक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा कर उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं व व्यक्तित्व निर्माण के सार्थक प्रयासों को व्यापक आधार देने का संकल्पबद्ध प्रयास किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता का व्यापकीकरण, वयस्क शिक्षार्थी की उसके सुविधानुसार स्थान व समय पर अनौपचारिक, जीवन्त व सार्थक शिक्षा उपलब्ध कराना, शैक्षिक अवसरों का समान वितरण, बालिका शिक्षा एवं महिला विकास को लोकप्रिय सुदृढ़ स्वरुप प्रदान करना, तकीनीकी एवं उच्च शिक्षा में आधुनिक प्रबन्ध व्यवस्था का समावेश कर उसे अधिक जनोपयोगी, समन्वित एवं प्रासंगिक बनाना, शिक्षा का स्तरोन्नयन तथा इसे सामाजिक सन्दर्भों से जोड़ना शिक्षा विभाग के प्रमुख उद्देश्य हैं। वर्ष 1991-92 का वर्ष शैक्षिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ एवं समेकित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि का वर्ष माना जा सकता है। आगामी पृष्ठों में शिक्षा सुविधाओं के यथोचित विस्तार की रुपरेखा प्रस्तुत की जा रही है। नामांकन वृद्धि, विद्यालयों तथा अनौपचारिक केन्द्रों की संख्या में बढ़ोतरी, विद्यालयों में भवन व पुस्तकालय सुविधा, खेल के मैदान व शारीरिक शिक्षा के उपकरणों में अभिवृद्धि, नवीन पदों के सृजन आदि से सम्बन्धित सूचनाएं एवं आंकड़े भी यथास्थान दिये गये है। शिक्षा के विस्तार के साथ-साथ शिक्षा का स्तरोन्नयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्तरोन्नयन की परिकल्पना अमूर्त होते हुए भी समाज के सभी घटकों पर अपनी प्रभावोत्पादकता स्पष्टतः अंकित करती है।

एक अन्य महत्वपूर्ण आयाम है सबके लिए शिक्षा। लोक जुंबिश योजना के अन्तर्गत इस दिशा मे एक अच्छी शुरुआत की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, श्रमिक बस्तियों में, सुदूर एकाकी ढाणियो में और उन समस्त अछूती बस्तियों में जहां विद्यालयी औपचारिक व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है वहाँ-वहाँ लोक-जुंबिश शिक्षा और साक्षरता का अलख जगाने के लिए पहुँच सकेगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। उन दुर्गम स्थानों पर जहाँ शिक्षकों का ठहराव न होने के कारण हजारों हजार छात्र शिक्षा और साक्षरता के मामले में कोरे रह जाते हैं, जहाँ परिवार की आर्थिक धूरी को सबल बनाये रखने में बालक-बालिकाओं को भी जुटना पड़ता है और जहाँ ऐसे अनेक बालक-बालिकाएँ औपचारिक विद्यालयों की समय सीमा से बाहर रह जाते को विवश हैं वहां शिक्षाकर्मी और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है। विशेष रुप से गत वर्ष के आंकड़ों में बालिका शिक्षा की जिस त्वरित गति का परिचय मिलता है उसके आधार पर आगामी वर्षों की गति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

व्यावसायिक शिक्षा के प्रारंभिक वर्ष उत्साहवर्धक कहे जा सकते हैं। गत शिक्षा सत्र में व्यावसायिक शिक्षा में विस्तार किया गया एवं उपलब्ध व्यवसायों की संख्या में वृद्धि की गई।

विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सतत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास इस बात के संकेत माने जा सकते हैं कि छात्र जीवन में जीविकोपार्जन, स्वरोजगार एवं उद्यम की प्रवृत्ति को यथेष्ट महत्व दिया जाये। विश्वविद्यालयीय शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया जाना तथा इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रबन्धकीय कौशल तथा प्रायोगिक पक्ष का समावेश किया जाना हमारे प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का विवरण इसी उद्देश्य की ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है।

विद्यालय एवं महाविद्यालय छात्र वर्ग को जो कुछ प्रदान करते हैं उसमें सांस्कृतिक चेतना एवं क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जन-सामान्य अपनी सांस्कृतिक अभिरूचियों की उपलब्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ना चाहता है। उसकी श्रीवृद्धि के लिए हम सभी प्रयासरत रहते है। प्राथमिक विद्यालयों से आरंभ कर विश्वविद्यालयी अध्ययन तक की यात्रा में इन सांस्कृतिक परम्पराओं को विस्तार मिलता रहे इस उद्देश्य से कतिपय अकादमियों का संचालन अराजकीय प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है।

राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी राजस्थान साहित्य अकादमी संस्कृत अकादमी, उर्दू अकादमी, सिन्धी अकादमी आदि का संक्षिप्त कार्यविवरण इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्राथमिक शिक्षा

राजस्थान राज्य शिक्षा की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। तथापि 1981 और 1991 के बीच जहां भारत का साक्षरता का प्रतिशत 8.55 बढ़ा है वहीं इसी अवधि में राजस्थान में साक्षरता प्रतिशत 8.72 रहा है, यह वृद्धि दर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से अधिक रही है। 1991 की जनसंख्या के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार राज्य का साक्षरता प्रतिशत 38.81 है जिसमें पुरुषों का 55.07 एवं महिलाओं का 20.84 प्रतिशत है।

मुख्य बिन्दुओं पर एक दृष्टिपात

1. राज्य में कुल प्राथमिक विद्यालय	31511	1991-92 में नये खोले गये विद्यालय	
		प्राथमिक विद्यालय	1359
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय	8,995	उच्च प्राथमिक विद्यालय	215
3. नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति			
सामान्य	*अनुसूचित जाति*		*अनुसूचित जनजाति*
(i) (6-11 आयुवर्ग)			
52.73 लाख	7.73 लाख		5.37 लाख
(ii) (11-14 आयुवर्ग)			
कुल—16.78 लाख	2.32 लाख		1.59 लाख
छात्राएं—4.21 लाख	0.35 लाख		0.26 लाख

4 वित्तीय स्वीकृतियाँ—

(i) उपस्थिति छात्रवृत्ति

राज्य के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर तथा नागौर जिलों में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन करने वाली छात्राओं को, जिनकी विद्यालयों में 75% एवं इससे अधिक उपस्थिति है, उन्हें 100/- प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।

कुल स्वीकृत राशि	*सामान्य क्षेत्र हेतु*	*जनजाति क्षेत्र हेतु*
60.00 लाख रु.	28.00 लाख	32.00 लाख
कुल लाभान्वित		
57,000 छात्राएं	25,000 छात्राएँ	32,000 छात्राएँ

(ii) अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु प्रोत्साहन

प्रति छात्र 90 रु. अर्थात् 30 रु. पुस्तकों एवं 60 रु. वर्दी हेतु।

स्वीकृत राशि	लाभान्वित कुल	सामान्य	अनुसूचित/जनजाति
75.00 लाख	83334	22000	61334

(iii) पाठ्यपुस्तकों हेतु स्वीकृति :–

स्वीकृत राशि – 50.40 लाख रु.

उद्देश्य–कक्षा 11 एवँ 12 के निर्धन एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जानजाति की बालिकाओं के लिए विद्यालयों में 5-5 सेट पुस्तकें उपलब्ध कराना।

(iv) स्पोर्ट्स होस्टल–

स्वीकृत राशि 2.17 लाख रु.

क्षेत्र जनजाति उपयोजना, क्षेत्र डूंगरपुर

(v) भामाशाह योजना में प्राप्त जन सहयोग –

प्राप्त राशि – 385.30 लाख रु.

राशि व्यय का क्षेत्र–विद्यालय भवन निर्माण, उपकरण, क्रय, पोषाक आदि

(vi)(क) राज्य आयोजन बजट से आवंटन–

आवंटित राशि 10.79 लाख रु.

व्यय का क्षेत्र 147 बालिका प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में फर्नीचर एवं साज-सामान हेतु।

(ख) राज्य योजना को जवाहर रोजगार योजना से जोड़ना

स्वीकृत राशि 1986.12 लाख

व्यय का क्षेत्र 4351 प्राथमिक विद्यालयों में पूर्ण अथवा आंशिक शाला भवन का निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में नामांकन वृद्धि, शिक्षण सुविधाओं का विस्तार, शिक्षण सामग्री के नवीनतम उपकरण, नये भवन निर्माण, शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, पाठ्यक्रमों का विकास, नई पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, माध्यमिक स्तर पर रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम, विज्ञान शिक्षाण में सुधार आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किए गए।

राज्य में बालक-बालिकाओं में धार्मिक सहिष्णुता एवं राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने की दृष्टि से नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कक्षा 1 से 5 में प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत कक्षा 1 व 2 के लिए नैतिक शिक्षा उपागम भाग–1 तथा कक्षा 3 के लिए नैतिक शिक्षा भाग–2 का अध्ययन कराया जा रहा है। कक्षा 4 व 5 के लिए 'छात्र डायरी' का निर्धारण किया गया। कक्षा 6 से 8 हेतु नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करवाकर एक विशिष्ट समिति द्वारा पठन सामग्री निर्मित करवाई जा रही है। कक्षा 9 व 10 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण एवं पाठन सामग्री निर्माण का कार्य करवाया जा रहा है।

विद्यालयों में भवन की कमी, अध्यापकों की समय पर विद्यालय में उपस्थिति, छात्र-छात्राओं का विद्यालय में ठहराव आदि समस्याओं के समाधान हेतु जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाने का प्रयास किया गया है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा जिलाधीशों की शिक्षा विभाग की समस्याओं को हल किए जाने हेतु दिए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक कलक्टर जिला स्तरीय समस्त शिक्षा अधिकारियों एवं उपखण्ड अधिकारियों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजत कर रहे हैं जिसमें अध्यापकों की कार्यस्थल पर उपस्थिति एवं अध्ययन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाती है। विद्यालयों में भवन के अभाव की पूर्ति हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध वित्तीय साधनों में से धनराशि भी जिला कलक्टर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

राज्य में नई स्थानान्तरण नीति लागू की गई जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की कठिनाइयों का निराकरण हुआ। विद्यालयों में अध्यापकों की मांग और पूर्ति के आधार पर कमी पूर्ति करने हेतु समानीकरण की योजना लागू कर पदस्थापन किया गये।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अपेक्षाओं के अनुरूप राज्य में कई नवीन कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्य में इकत्तीस हजार पाँच सौ ग्यारह प्राथमिक तथा आठ हजार नौ सो पिचानबे उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत हैं। वर्ष 91-92 में औपचारिक शिक्षा के 6-11 आयुवर्ग का नामांकन लक्ष्य 52.73 लाख, अनुसूचित जाति का नामांकन लक्ष्य 7.73 लाख व अनुसूचित जनजाति का नामांकन लक्ष्य 5.37 लाख का है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति संभवतया मार्च, 1992 तक कर ली जायेगी।

11-14 आयुवर्ग के समस्त जाति के बच्चों के लिए वर्ष 1991-92 में नामांकन लक्ष्य 16.78 लाख रखा गया जिसमें 4.21 लाख छात्राएं हैं। अनुसूचित जाति के छात्रों का वर्ष 1991-92 का नामांकन लक्ष्य 2.32 लाख है जिसमें छात्राएं 0.35 लाख हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के छात्रों का नामांकन लक्ष्य वर्ष 1991-92 का 1.59 लाख है, जिसमें छात्राएं 0.26 लाख है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति संभवतया मार्च, 1992 तक कर ली जायेगी।

जनजाति क्षेत्र एवं बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एवं नागौर में कक्षा 1 सौ 5 में अध्ययन करने वाली छात्राओं की 75% एवं इससे अधिक की उपस्थिति पर छात्रवृत्ति हेतु 60.00 लाख रु. स्वीकृत करवाये गये जिसमें से 28 लाख रु. सामान्य क्षेत्र के लिए एवं 32 लाख रु. का प्रावधान जनजाति क्षेत्र के लिए रखा गया, जिसका आवंटन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को किया जा चुका है। इस राशि से कुल 25,000

सामान्य क्षेत्र की तथा 32,000 जनजाति क्षेत्र की छात्राएं लाभान्वित होंगी। अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रति छात्र 30 रु. पाठ्यपुस्तकों एवं 60 रु. पोषाक के लिए दिए जाने हेतु 75 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इस राशि से सामान्य क्षेत्र के 22,000 एवं जनजाति क्षेत्र के 61334 छात्र/छात्राएं लाभान्वित होंगे।

कक्षा 11 एवं 12 की निर्धन बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों के लिए विद्यालयों में पुस्तकों के 5-5 सेट उपलब्ध कराने हेतु 50.40 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के डूँगरपुर जिले में एक 'स्पोर्टस होस्टल' शुरु किए जाने हेतु 2.17 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गई।

भामाशाह योजनान्तर्गत वर्ष 91-92 में विद्यालय भवन निर्माण कक्षा, कक्षा-कक्ष निर्माण, उपकरण, छात्र गणवेश आदि के लिए 358.30 लाख रु. का जनसहयोग प्राप्त किया गया। इस योजना अन्तर्गत राजस्थान के प्रवासी भाईयों को भी विकास की धारा से जोड़ने की पहल द्वारा जनसहयोग के क्षितिज का विस्तार किया गया।

वर्ष 1991-92 के आयोजना बजट में 147 बालिका प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में फर्नीचर एवं साज-सामान देने हेतु 10.79 लाख रु. की राशि का आवंटन किया गया। राज्य योजना को जे. आर. वाई. से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के 4315 प्रा.वि. में पूर्ण एवं आंशिक शाला भवन निर्माण हेतु 1986.12 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई जिसका कार्य मार्च, 92 तक पूरा कर लिया जायेगा।

वर्ष 91-92 में 1000 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा तथा था जिसके विरुद्ध 1359 प्राथमिक विद्यालय खोले गये तथा 150 प्राथमिक विद्यालयों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया था जिसके विरुद्ध कुल 215 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया।

आपरेशन ब्लेक बोर्ड

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु राज्य में यह कार्यक्रम वर्ष 1987-88 से प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत एकल अध्यापकीय शालाओं में दूसरा अध्यापक, विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सामग्री तथा भवन सुविधाओं में न्यूनतम कम से कम दो कक्षा कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 237 पंचायत समितियों तथा शहरी क्षेत्र के 27014 विद्यालयों को लिया गया। इस वर्ष 5129 एकल अध्यापकीय शालाओं को दो अध्यापकीय शालाओं में बदलने हेतु 5129 अध्यापकों के पद उपलब्ध कराए गए तथा 96 पंचायत समितियों के विद्यालयों को न्यूनतम आवश्यक सामग्री दिए जाने हेतु 398.13 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गई।

अनौपचारिक शिक्षा

9-14 आयुवर्ग के ऐसे बालक-बालिकाएँ जो सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक परिस्थितियों के कारण विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रहते हैं, उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था है। राज्य में 10684 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से 3.05 लाख बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है जिसमें 0.66 लाख अनुसूचित जाति एवं 0.61 लाख अनूसूचित जनजाति के हैं। बालिकाओं के

नामांकन की वृद्धि हेतु 3000 बालिका केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 6000 किया गया। आलोच्य वर्ष में 3700 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का प्रोजज्टाइजेशन किया गया।

शिक्षाकर्मी योजना

दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों में बालक-बालिकाओं की प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु स्वीडिश इन्टरनेशनल विकास एजेन्सी के सहयोग से राज्य में शिक्षाकर्मी योजना वर्ष 1987-88 से लागू की गई है। यह योजना प्रारम्भ में 12 पंचायत समतियों के 120 विद्यालयों तथा 240 रात्रि विद्यालयों (प्रहर पाठशालाओं) में प्रारम्भ हुई। वर्तमान में यह योजना 17 जिलों में चलाई जा रही है। 415 दिवस-विद्यालय तथा 706 प्रहर-पाठशालाएँ संचालित हैं, जिनमें क्रमशः 24327 व 11468 छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के अध्ययन से पाया गया है कि दिवस-विद्यालयों के नामांकन में 35% की वृद्धि हुई तथा बालक-बालिकाओं का विद्यालय से ठहराव 51% से बढ़कर 78% हो गया।

लोक जुम्बिश

स्वीडिश इन्टरनेशनल विकास एजेन्सी, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के 3:2:1 के अनुपात में सहयोग से सभी के लिए शिक्षा सन् 2000 तक की योजना प्रारम्भ की जा रही है। इन योजना में 10 वर्षों में 600 करोड़ रुपया व्यय होगा। आलोच्य वर्ष में इस योजना की प्रारम्भिक तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई हैं। दो पंचायत समितियों के 10-10 गांवों में चेतना शिविर लगाए गए हैं तथा अन्य तीन पंचायत समितियों के लिए स्टाफ का चयन एवं पदस्थापन भी हो चुका हैं।

अप्रेल, 92 से जून 1994 तक प्रथम चरण में 20 करोड़ रुपयों की कार्य योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है।

माध्यमिक शिक्षा

वर्ष 91-92 सत्र के 62 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया गया। बालिकाओं को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 21 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। इस वर्ष 131 राजकीय उ. प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया जिनमें 36 बालिका विद्यालय सम्मिलित हैं। इस वर्ष के दौरान 23 विषय एवं 19 संकाय राजकीय सी. उच्च. माध्य. विद्यालयों में खोले गए। महिला एंव अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों हेतु 684 विद्यालयों में 15.39 लाख की पाठ्यपुस्तकें, सामग्री आदि उपलब्ध कराई गई। 2011 माध्यमिक विद्यालय एवं 684 सीनियर हायर सैकण्डरी में कक्षा फर्नीचर हेतु 539.00 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई।

75 विद्यालयों में 158 कक्षा-कक्ष तथा प्रयोगशाला कक्ष निर्माण हेतु 100 लाख रु. उपलब्ध कराए गए।

प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कार

बोर्ड को परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले छात्र/छात्राओं को वर्ष 91-92 में 2.82 लाख आवंटन किया गया। उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों को 1000/- रु. एव माध्यमिक स्तर के छात्रों को 600/- रु. के हिसाब से राशि का आवंटन किया गया।

छात्र-वृत्तियां

शिक्षा विभाग के बजट से विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए 27.42 लाख रु. स्वीकृत किए जा रहे हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियो की प्रदत्त पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उच्च प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में आवासीय सुविधा सहित 769 छात्र-छात्राओं का चयन किया जाकर समाज कल्याण विभाग के बजट से 60.00 लाख रुपये छात्रवृत्ति के स्वीकृत किए गए हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों की योग्यता अभिवृद्धि

भारत सरकार के सहयोग से राज्य के तीन सी. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसमें 40 अनूसूचित जाति के तथा 27 अनूसूचित जनजाति के छात्रों की प्रतिवर्ष कक्षा-9 में योग्यता के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। इस योजना में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अतिरिक्त कक्षाओ के द्वारा विषयों का अध्यापन, आवास व्यवस्था, भोजन का व्यय, पाठ्यपुस्तकों तथा फीस आदि की सुविधा

छात्रों को उपलब्ध कराई जाती है।

विद्यालयों में विषय परिषदें

प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय परिषदों के माध्यम से छात्रों की स्वाध्याय प्रवृत्ति तथा व्यक्तित्व विकास के लिए क्लास सेमीनार की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था से बच्चों को स्वयं सीखने, पुस्तकालय का लाभ उठाने तथा आपस में विचार-विमर्श करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

पाठक-मंच

पुस्तकालयों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके इसके लिए विद्यालयों में पाठक-मंच की योजना प्रारम्भ की गई। इसके माध्यम से माह में एक या दो बार छात्र-छात्राओं को नियमित विषय अथवा विचार बिन्दु पर अध्ययन करने तथा बोलने का अवसर मिल रहा है। इससे विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास हो रहा है।

विद्यालय और जिला योजना

विद्यालय एवं जिला योजना का निर्माण एवं क्रियान्वियन विभाग पहले से ही कर रहा था। लेकिन इस योजना का स्वरूप केवल कागजी बन कर रह गया था। इस योजना की पुनः सक्रिय स्वरूप दिए जाने के प्रयास विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। इस क्रम में विद्यालय योजना और जिला योजना का संशोधित प्रारूप शिविरा पत्रिका में प्रकाशित करवाया गया। प्रधानाध्यापक वाक्पीठ की बैठकों में विद्यालय योजना एवं जिला योजना के प्रभाव व क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चाएं करवाई गई। इसके अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

ट्यूटोरियल

शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने हेतु ट्यूटोरियल कक्षाएँ नवाचार के रूप में प्रारम्भ की गई। वर्ष 90-91 में यह कार्यक्रम 107 विद्यालयों में चलाया गया जिसमें 1521 अध्यापक/अध्यापिका ने अपनी विशिष्ट सेवाएं दी तथा 39622 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए। वर्ष 1991-92 में इस कार्यक्रम का अधिक विस्तार किया गया। इस वर्ष 374 छात्र तथा 133 छात्रा माध्यमिक/सीनीयर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ट्यूटोरियल कक्षाएँ प्रारम्भ को गई। इसके अन्तर्गत 3251 अध्यापक/अध्यापिकाएँ अपनी सेवाएँ दे रही हैं तथा 80195 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

15-35 आयुवर्ग के 25 लाख प्रौढ़ों की आठवीं पंचवर्षीय योजना में साक्षर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु वर्ष 91-92 में राज्य में 4.32 लाख प्रौढ़ों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। आलोच्य वर्ष में राज्य में 13643 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं जिसमें 2.02 लाख प्रौढ़ों को साक्षर किया जा रहा है। इस सत्र में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत गति प्रदान की गई। अच्छे वातावरण हेतु प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण शिक्षा समितियों की स्थापना की गई है। साक्षरता को अन्य विभागों से जोड़ा गया है जिसमें पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वायत्त शासन संस्थाएं

तथा होमगार्ड आदि की भूमिका प्रमुख हैं। भूतपूर्व सैनिकों को व्यापक साक्षरता कार्यक्रम से जोड़ा गया है तथा जेल विभाग के सहयोग से भी राज्य के विभिन्न जिलों में प्रौढ़ शिक्षा के केन्द्र संचालित हैं। इन सभी कार्यक्रमों के अच्छे परिणाम निकले हैं।

साक्षरता विकास के प्रयासों को सघन करते हुए अजमेर जिले को सम्पूर्ण साक्षर करने के लक्ष्य के अन्तर्गत 4.06 लाख प्रौढ़ों की साक्षर किया गया है तथा 470 ग्राम व शहरी क्षेत्रों के 42 वार्डों को सम्पूर्ण साक्षर किया गया हैं। साथ ही भरतपुर, डूँगरपुर एवं सीकर जिलों को सम्पूर्ण साक्षर करने हेतु कार्यक्रम की प्रारम्भिक तैयारियां तीव्र गति से क्रियान्वित की जा रही हैं। इन जिलों में पाठ्य सामग्री का निर्माण कराया जा रहा हैं।

जनशिक्षण निलयम

राज्य में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 2220 जनशिक्षण निलयम कार्य कर रहे हैं। जन शिक्षण निलयम उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के साथ-साथ सामुदायिक जन जागृति केन्द्र का कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों पर पुस्तकालय एवं वाचनालय की सेवाओं के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियां, सांध्य कक्षाएं, वार्ताएं, तथा चर्चा मण्डलों का आयोजन भी किया जाता है। रेडियो/टेलीविज़न की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

राज्य में वर्तमान में 118 विद्यालयों में यह कार्यक्रम चल रहा है। इनके अतिरिक्त तीन अराजकीय संस्थाओं में भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन सभी में 21 पाठ्यक्रम स्वीकृत हैं। ये पाठ्यक्रम विद्यालयों में 321 व्यावसायिक कक्षाओं के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष 91-92 में 20 नए विद्यालयों में 60 नए पाठ्यक्रम तथा 54 अतिरिक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जा रहे हैं। राज्य में व्यावसायिक शिक्षा को गति प्रदान करने की दृष्ट से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद का गठन हो चुका है। इसके अलावा अन्तरविभागीय स्टेट कौंसिल ऑफ एज्युकेशन भी कार्यरत है।

विज्ञान सुधार कार्यक्रम

राज्य के 13 जिले इस योजनान्तर्गत लिए जा चुके हैं। 14 जिलों को चरणवार भारत सरकार की योजनानुसार लिए जाने का प्रयास किया जा रहा हैं। इस वर्ष भारत सरकार 5 नवीन जिलों के लिए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किए गए हैं। इस योजना में प्रयोगशाला निर्माण, विज्ञान उपकरण, विज्ञान पुस्तकें तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए विज्ञान् किट, दिए जाने का प्रावधान है।

सीमान्त क्षेत्रीय शैक्षिक विकास कार्यक्रम

भारत सरकार के शत प्रतिशत सहयोग से यह कार्यक्रम चार सीमान्त जिलों की 13 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। इस वर्ष इनके नजदीक की तीन अतिरिक्त पंचायत समितियां भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, अध्यापक आवास, लड़कियों के लिए चार छात्रावास, न्यूनतम आवश्यक सामग्री एवं फर्नीचर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 596 प्राथमिक, 26 उच्च प्राथमिक एवं 13 माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं।

उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु इस वर्ष भारत सरकार द्वारा दस करोड़ रुपयों का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

शिक्षक प्रशिक्षण

वर्तमान में राज्य में 38 बी. एड्. महाविद्यालय हैं। बी. एड्. में इस वर्ष 4580 सीधी भर्ती से तथा 157 सेवारत अध्यापकों को प्रवेश दिया गया। राज्य में वर्तमान में 11 एम. एड. महाविद्यालय हैं इनमें कुल 262 सीटें हैं। इस वर्ष सीटें और बढाई गई हैं।

राज्य में दो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर व अजमेर में हैं तथा एक सी. टी. ई. जोधपुर में केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत है। इनमें बी. एड्. एवम् एम. एड्. पाठ्यक्रम चलने के साथ वर्ष भर सेवारत अध्यापकों के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्य में 27 जिलों में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जा चुके हैं।

पर्यावरण

शिक्षा को भौतिक प्रगति से जोड़ने एवं पर्यावरण के प्रति सजग बनाने हेतु राज्य के विद्यालयों के माध्यम से गाँव की पड़त गोचर या सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में वर्ष 90-91 में 2.38 लाख पेड़ लगाए गए। वर्ष 1991-92 में 14.25 लाख पौधे लगाए गए जिसमें से 12.88 लाख पौधे जीवित हैं। नर्सरी निर्माण के अन्तर्गत 4.80 लाख के विरुद्ध 5.92 लाख पौधों के लक्ष्य प्राप्त किए गए।

माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर तथा जिला स्तर पर पर्यावरण से जुड़ी साक्षरता सोसाइटीज़ पंजीकृत कराने की कार्यवाही की जा रही है। वन एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के द्वारा पर्यावरण सौन्दर्यीकरण एवं साक्षरता प्रयासों की एकीकृत स्वरूप प्रदान किए जाने की कार्यवाही चल रही है।

शारीरिक शिक्षा

पर्वतारोहण हेतु वर्ष 91-92 के लिए 50000 की राशि का प्रावधान है। जिसके लिए छात्र छात्राओं को साहसिक अभियान के अन्तर्गत 'डेजर्टसफारी' ट्रेकिंग अभियान तथा स्नो-स्कींग कार्यक्रम प्रस्तावित किए हुए हैं।

समाज शिक्षा एवं पुस्तकालय

वर्ष 91-92 के दौरान रिज़र्व बुक योजना अभियान चलाकर दान दाताओं से 450 पुस्तकें एकत्र की गई। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष में पुस्तकालय में फर्नीचर क्रय हेतु 35000 रुपये का आवंटन किया गया। विद्यालयों के पुस्तकालय उपयोगार्थ 3.06 लाख की पुस्तकें क्रय की गई। चित्तौड़गढ़ में जिला पुस्तकालय 5.00 लाख की लागत से बनाया गया।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, उदयपुर

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर शिक्षा की गुणवत्ता वृद्धि के प्रयास करने एवं प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीनीकरण के लिए क्रियाशील अग्रगामी संस्थान है। संस्थान के आधारभूत दायित्व में—प्रशिक्षण, सामग्री विकास, अनुसंधान प्रसार एवं प्रकाशन के कार्य हैं। अब तक संस्थान प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध था लेकिन पिछले वर्षों से संस्थान के कार्य क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन-प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध हुआ। बदली हुई परिस्थितियों में संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों की सफल क्रियान्विति कर एक अग्रगामी संस्थान के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

मुख्य बिन्दु

1. विज्ञान शिक्षण सुधार योजना
   - उच्च प्राथमिक स्तर
   - गणित एवं विज्ञान— विज्ञान एवं गणित के 80 शिविरों में क्रमशः 1782 तथा 1935 शिक्षकों का प्रशिक्षण।
   - माध्यमिक स्तर— विज्ञान एवं गणित के 46 शिविरों में 1165 शिक्षक लाभान्वित।
2. अनौपचारिक शिक्षा
   - 35 परियोजनाओं के 3500 अनुदेशकों का प्रशिक्षण।
   - 196 डाइट्स के प्राचार्य अनौपचारिक शिक्षा के मुख्य सन्दर्भ व्यक्ति एवं परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण।
   - फरवरी माह में 9300 अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण।
   - हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, सिन्धी एवं विज्ञान के 16 शिविरों में 499 शिक्षक लाभान्वित।
3. जिला सन्दर्भ केन्द्र (अंग्रेजी) एवं अंग्रेजी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम—450 शिक्षक लाभान्वित।
4. व्यावसायिक शिक्षा—253 शिक्षकों को भोजन परिरक्षण एवं क्रेश व्यवसायों में प्रशिक्षण
5. राजस्थान राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर एवं नीपा के शैक्षिक कार्यक्रम।
6. जनसंख्या शिक्षा, प्रायोजना।
7. कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम की आवश्यकतानुसार नवीन पाठ्यपुस्तकों का निर्माण।
8. प्रधानाध्यपकों का प्रशिक्षण—81 नये प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण।

प्रतिवेदित अवधि में संस्थान ने शैक्षिक विकास को गति देते हुए जो विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनका विवरण निम्नांकित है–

(1) विज्ञान शिक्षण सुधार योजना

केन्द्र प्रवर्तित योजना–विज्ञान शिक्षण सुधार योजना के अन्तर्गत मानव संसाधनों के विकास की दृष्टि से 8.13 लाख रुपयों की स्वीकृति हुई थी। इस राशि का उपयोग करने के लिए राज्य के नौ जिलो के विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए।

इस महत्वाकांक्षी योजना में उदयपुर चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, सिरोही, जैसलमेर और नागौर जिलों के उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मिलित किया गया। दोनों विषयों के 160 शिविर 4 मार्च, 91 से 2 नवम्बर 91 तक संचालित किए गए। उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान के 80 शिविरों में 1782 शिक्षकों को एवं गणित के 80 शिविरों में 1935 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

माध्यमिक स्तर के विज्ञान एवं गणित पढाने वाले शिक्षकों के 15 दिवसीय शिविरों का आयोजन उपर्युक्त अवधि में किया गया। दोनों विषयों के 46 शिविरों में 1165 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(2) अनौपचारिक शिक्षा

अनौपचारिक शिक्षा के सशक्त विकल्प के रूप में अनौपचारिक शिक्षा की क्रियान्विति की जा रही है। दिसम्बर 89 से प्रोजेक्टाइजेशन के अन्तर्गत राज्य में एक नई योजना प्रारंभ की गई। इसके अन्तर्गत सघन परिवीक्षण की दृष्टि से समूहों का निर्माण कर पुराने केन्द्रों को नए केन्द्रों के साथ मिलाते हुए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को गति दी गई। इस चरण में 40 परियोजनाएं स्वीकृत की गई। प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरणों में 102 परियोजनाएं, 165 पंचायत समितियों में स्वीकृत है। सितम्बर 91 में स्वीकृत 35 परियोजनाओं के 3500 अनुदेशकों के प्रशिक्षण-योजना की क्रियान्विति चल रही है।

एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (ग्रामीण) सहायक निदेशक, अनौपचारिक शिक्षा को मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण एवं परियोजना अधिकारी प्राचार्य डाइट, उप प्राचार्य डाइट, व्याख्याता डाइट, पर्यवेक्षक संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार लाभान्वितों की संख्या 196 है।

सामग्री विकास की कार्यगोष्टियों एवं समीक्षा कार्य गोष्ठियों में 156 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 10 फरवरी, 92 तक 310 अनुदेशक प्रशिक्षण शिविर संचालित किए जा रहे हैं जिनमें लगभग 9300 अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

(3) भाषा उन्नयन-प्रशिक्षण कार्यक्रम

भाषा शिक्षण के उन्नयन की दृष्टि से ग्रीष्मकालीन उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए 28 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी एवं विज्ञान विषयों के 16 शिविरों के लिए परामर्शद एंवं संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। तीन दिवसीय 6 कार्यक्रमों में 52 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 13 शिविरों में 499 शिक्षक लाभान्वित हुए।

(4) जिला संदर्भ केन्द्र (अंग्रेजी)

केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत जिला संदर्भ केन्द्र (अंग्रेजी) का संचालन केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद के आर्थिक सहयोग एवं निर्देशन में हो रहा है। संस्थान में जिला संदर्भ केन्द्र (अंग्रेजी) की स्थापना जन. 89 में हुई. प्रतिवेदित अवधि में माध्यमिक कक्षाओं को अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों के दस दिवसीय. प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। दस दिवसीय 5 अभिनवन कार्यक्रमों में 252 शिक्षक लाभान्वित हुए। एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम सम्पर्क कार्यक्रम में 78व्यक्ति लाभान्वित हुए एवं केन्द्रों पर अनुगमन कार्यक्रम में 100 शिक्षक लाभान्वित हुए।

(5) अंग्रेजी सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की क्रियान्विति भी केन्द्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद के तत्वावधान में संस्थान में की जा रही है। अंग्रेजी शिक्षण अभिनवन कार्यक्रम (जनजाति क्षेत्र मा. वि.) अजमेर मंडल के अंग्रेजी व्याख्याताओं के लिए बारह दिवसीय कार्यक्रम एवं अंग्रेजी व्याख्याता संदर्भ व्यप्त कार्यक्रम एवं अंग्रेजी व्याख्याता अभिनवन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन तीनों कार्यक्रमों में 111 शिक्षक लाभान्वित हुए। शिक्षकों का 28 दिवसीय अभिस्थापन कार्यक्रम के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसामग्री विकास, समीक्षा एवं नवनीनीकरण हेतु 5-5 दिवसीय 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 11 व्यक्तियों ने भाग लेकर कार्य पूर्ण किया।

(6) कला शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में स्कूली शिक्षा में कला शिक्षा का एक आयाम और जुड़ा है। इसी की क्रियान्विति हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं एवं एस. टी. सी. के कला शिक्षकों का अभिस्थापन कार्यक्रम (6 दिवसीय) आयोजित किया गया जिसमें 21 व्याख्याताओं एवं कला शिक्षकों ने भाग लिया। राज्य में पहली बार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कला शिक्षण करने वाले शिक्षकों का 28 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोवर्धन विलास (उदयपुर) में आयोजित किया गया।

माध्यमिक स्तर पर कला शिक्षण के पाठ्यक्रम को विकसित करने का कार्य अब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा नहीं किया जा सका था। संस्थान ने प्रतिवेदित अवधि में यह पाठ्यक्रम विकसित कर बोर्ड को भिजवाया है।

(7) व्यावसायिक शिक्षा

(अ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दस्तावेज में 10+2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की सुदृढ क्रियान्विति पर बल दिया है। राजस्थान राज्य में व्यावसायिक शिक्षा सत्र 87-88 में प्रारंभ की गई प्रारंभ में 10+2 स्तर पर 52 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालय प्रारंभ किए गए। राज्य के 30 जिलों के 128 सी. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

संस्थान का व्यावसायिक शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम निर्माण एवं मानव संसाधनों के विकास के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करता है।

प्रतिवेदित अवधि में सर्वेक्षण कार्य प्रशिक्षण, उप प्रधानाचार्य (व्या. शि.) अभिनवन, व्यावसायिक शिक्षा (वाणिज्य संकाय के 5 विषय एवं व्यावसायिक शिक्षा संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम भोजन परिरक्षण एवं क्रेश) के कुल 14 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 253 शिक्षक लाभान्वित हुए।

(ब) कार्यानुभव—कार्यानुभव को उच्च प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का अंग माना गया है। प्रतिवेदित अवधि में कार्यानुभव के अन्तर्गत-डाइट के कार्यानुभव संदर्भ्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं कक्षा 9, 10 कार्यानुभव प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्माण के 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 90 शिक्षक लाभान्वित हुए।

मनोवैज्ञानिक आधार तथा शैक्षिक. एवं व्यावसायिक निर्देशन—

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन को प्रभाविक ढंग से आयोजित करने की अनुशंषा की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 5 प्रमुख शहरों (कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर) में शैक्षिक एवं व्यावसायि निर्देशन कक्ष खोले गए हैं। पत्राचार द्वारा भी मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

जिला स्तरीय निर्देशन समारोह एवं प्रदर्शनियों का आयोजन किये जाने के बाद राज्य स्तरीय निर्देशन समारोह एवं प्रदर्शनी का आयोजन जोधपुर में किया गया जिसमें22,000छात्र-छात्राओं, नागरिकों ने अवलोकन कर लाभ उठाया। प्रशिक्षण के 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें118 शिक्षक लाभान्वित हुए।

(8) एन.सी.ई.आर.टी., नीपा एवं सी.सी.आर.टी. के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन

राष्ट्रीय स्तर की इन शैक्षिक संस्थाओं से समन्वय एवं सहयोग प्राप्त कर सप्लीमेन्ट्री रीडर लेखन (नारी की विकास यात्रा) बाल भारतीय की सप्लीमेन्ट्री रीडर लेखन, अनौपचारिक शिक्षा, मुख्य संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनौ. शिक्षा केन्द्रों के लिए चित्रात्मक पूरक लेखन सामग्री निर्माण, डाइट के समन्वयकों का राज्य स्तरीय अभिनवन कार्यक्रम, डाइट के सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री निर्माण के 11 कार्यक्रम संस्थान में एन. सी. ई. आर. टी. नई दिल्ली द्वारा संस्थान में आयोजित किए गए जिनमें 378 शिक्षक लाभान्वित हुए। सी. सी. आर. टी. द्वारा समाजोपयोगी उत्पादन कार्य एवं कार्यानुभव के शिविर कठपुतली अभिनवन शिविर तथा प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा के परिरक्षण में विद्यालयों की भूमिका शिविरों का आयोजन किया जिनमें 1478 छात्र-छात्राएं एवं अध्यापक अध्यापिकाएं लाभान्वितु हुए। नीपा द्वारा डाइट के आयोजन एवं प्रबन्ध शाखा के प्रभारियों का तीन सप्ताह का सघन प्रशिक्षण आयोजित किया गया जिसमें 44 अधिकारियों ने भाग लिया। इन तीनों संस्थाओं के शैक्षिक कार्यक्रमों में 1900 छात्र-छात्राएं एवं शिक्षक लाभान्वित हुए।

(9) विदेशों के अध्ययन दलों द्वारा संस्थान के क्रियाकलापों का अवलोकन

राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों द्वारा संस्थान का अवलोकन होता रहा है। प्रतिवेदित अवधि में शिक्षा के कार्यक्रमों की उपलब्धियों का जायजा लेने भारत सहित नेपाल, भूटान, श्री लंका, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, ईरान एवं मारीशस के दलों ने संस्थान का अवलोकन किया। साथ ही फरारा और भूवाणा की संस्थाओं का अवलोकन भी किया गया।

(10) राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन

राज्य स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन इस वर्ष 6 जनवरी, 92 से 10 जनवरी, 92 तक पोद्दार सी. उ. मा. वि. जयपुर में आयोजित किया गया। 124 वें राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में 6 उप विषयों के मंडप लगा कर प्रदर्श रखे गए थे।

इस मेले में सबके लिए भोजन, भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी, ऊर्जा परिदृश्य, पर्यावरण, सबके लिए स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित 269 मॉड्ल प्रस्तुत किए गए। 380 छात्रों एवं 70 छात्राओं ने भाग लिया।

(11) राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की पूर्व तैयारी के लिए प्रतिवर्ष मार्गदर्शन शिविर आयोजित करने एवं साक्षात्कार लेने का कार्य संस्थान द्वारा किया जाता है। इस वर्ष जयपुर और उदयपुर में मार्ग दर्शन शिविरों का आयोजन किया गया जिनमें 137 छात्रों ने भाग लिया। प्रतिभा खोज साक्षात्कार में 97 छात्र प्रविष्ट हुए जिनमें से 43 छात्रों ने वरीयता सूची में स्थान बनाते हुए सफलता प्राप्त की।

(ब) ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा

ग्रीमीण प्रतिभाओं की प्रोत्साहित करने एवं उन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष संस्थान द्वारा ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाता है। छात्रवृत्ति परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने एवं जिला स्तर पर परीक्षा लेने हेतु व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई। इस वर्ष लगभग 17578 छात्रों ने इस परीक्षा हेतु अपना नामांकन करवाया था।

(12) जनसंख्या शिक्षा प्रायोजना

संस्थान में विद्यालयी छात्र-छात्राओं में जनसंख्या संतुलन की जागरुकता पैदा करने की दृष्टि से जनसंख्या शिक्षा प्रायोजना की क्रियान्विति की जा रही है। प्रतिवेदित अवधि में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिए अनुदेशकों के लिए पाठ्य सामग्री एवं पूरक पठन सामग्री तैयार करने के लिए 11 कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिनमें 96 शिक्षकों ने भाग लिया। इसके अलावा कोर पेकेजेज़ का हिन्दी अनुवाद कार्य भी सम्पन्न किया गया। मूल्यांकन एवं अनुसंधान के 2 कार्यक्रम आयोजित हुए जिनमें 20 शिक्षकों ने भाग लिया। डाइट एवं के. एफ. आई. सी. ब्रांच के वरिष्ठ व्याख्याताओं के लिए जनसंख्या शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं दो कार्यक्रम मा. वि. के प्राध्यापकों हेतु आयोजित किए गए। इन तीनों कार्यक्रमों में 64 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

(13) सामुदायिक विज्ञान केन्द्र

जनसाधारण की विज्ञान की जानकारी देने एवं वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न करने की दृष्टि से सहेलियों की बाड़ी सामुदायिक विज्ञान केन्द्र की स्थापना 1969 में की गई थी। वर्ष 1986 में विज्ञान एवं प्रौद्यागिकी विभाग एवं संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों एवं महिलाओं में विज्ञान की चेतना प्राप्त करने हेतु कई कार्यक्रम संचालित किए गए हैं जिनमें महिला शिविर, परैंडा प्रतियोगिता, स्वच्छ शिशु प्रतियोगिता,

माडल मेकिंग कार्यशाला एवं विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन मुख्य है।

प्रतिवेदित अवधि में सालेरा, रेलमगरा, ओवरा खुर्द, छाणी और नाई ग्रामों का चयन कर "विज्ञान की दस्तक गाँव की दहलीज पर" कार्यक्रम संचालित किया गया। प्रति वर्ष सहेलियों की बाड़ी स्थित सामुदायिक केन्द्र का डेढ लाख स्त्री-पुरुषों द्वारा अवलोकन किया जाता है।

(14) शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार

शैक्षिक अनुसंधान की गति देने की दृष्टि से प्रतिवेदित अवधि में शिक्षा अनुसंधान विधि शास्त्र का दस दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 31 संभागियों ने भाग लिया। डर्फ सचिवों के लिए विधि शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 18 जिलों के 30 संभागी उपस्थित हुए। संस्थान के अन्य विभागों के सहयोग से 13 प्रकरणों पर अध्ययन किया जा रहा हैं। डर्फ के 55 शोध प्रस्तावों के लिए 11200 रु. का आंशिक अनुदान दिया गया है।

(15) नवीन पाठ्यपुस्तकों का प्रणयन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में कोर एलिमेंट्स को ध्यान में रख कर तीन चरणों में पहली से आठवीं तक की 79 पाठ्य पुस्तकों का लेखन करवाया जाकर उनकी समीक्षा करवाई गई है। इसके बाद राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गई है। पहले चरण में पहली, तीसरी एवं छठी कक्षा की 26 पाठ्य पुस्तकें, दूसरे चरण में दूसरी, चौथी एवं सातवीं की 14 पाठ्य पुस्तकें एवं तीसरे चरण में पांचवी एवं आठवीं की 13 पुस्तकें तैयार की जाकर राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी गई। शेष अभी प्रक्रियाधीन हैं।

(16) विकलांग एकीकृत शिक्षा प्रायोजना (छबड़ा प्रोजेक्ट)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में विकलांग बालकों को एक समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था के अन्तर्गत यह प्रायोजना बारां जिले की छबड़ा पंचायत समिति के स्कूलों में संचालित की जा रही है। 1987 में प्रारंभ की गई इस प्रायोजना की संकल्पना से प्रतिवेदित अवधि में 87 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इस वर्ष 663 छात्र-छात्राएं (विकलांग) नामांकित हुए हैं। अभिभावक संपर्क कार्यक्रम एवं अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कुल 4186 अभिभावक लाभान्वित हो चुके हैं। पंचायत समिति के 134 विद्यालयों में विकलांग बालकों से संबंधित उपकरण खिलौने आदि उपलब्ध कराए।

(17) संस्थान के प्रकाशन

संस्थान के उपलब्ध बजट का उपयोग करते हुए प्रतिवेदित अवधि में 13 प्रकाशन करवाए गए। प्रधानाध्यपक (मा. वि.) संदर्शिका राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के मॉडलों की पुस्तिका, वार्षिकी, मूल्य परक शिक्षा, छात्र डायरी, अनुसंधान अंक 3, पर्यावरण पुस्तिका कक्षा 3 एवं ब्रोशर्स एवं अंग्रेजी बुलेटिन मुख्य हैं।

(18) भौतिक संसाधनों की अभिवृद्धि

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर लगवाया गया। डेटा प्रोसेसिंग एवं प्रोग्रामिंग के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 10 लाख की राशि कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर कक्ष के लिए विचाराधीन है। शैक्षिक कार्य सम्पादन एवं संस्थानिक कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित करने

हेतु निदेशालय में कार्यरत 30 कनैक्शन वाला पी. बी. एक्स संस्थान सें लगवाया गया है। जनसंख्या शिक्षा प्रायोजना द्वारा इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर एवं फोटो कापियर लगाया गया है।

(19) प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम

शिक्षा सेवा में नव चयनित प्रधानाध्यापकों को पूर्व में 15 दिन का अभिस्थापन कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। अकादमिक एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग सें हो सके इस दृष्टि से आठ सप्ताह का गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण में प्रतिबद्धता कार्यक्रम भी रखा गया है। संस्थान द्वारा प्रतिवेदित अवधि में आठ सप्ताह के दो प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। पहला शिविर दिनांक 19.8.91 से 10.10.91 तक आयोजित किया गया जिसमें 38 प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया। दूसरा शिविर दिनांक 6.1.92 से 29.2.92 तक आयोजित किया गया। जिसमें 43 प्रधानाध्यापक प्रशिक्षित किए गये।

(20) नॉडल एजेन्सी एवं प्रबोधन

संस्थान विभिन्न अकादमिक कार्यों को गति देने हेतु समन्वय एवं सहयोग की दृष्टि नॉडल एजेन्सी के रूप में कार्य करता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सेवारत एवं सेवापूर्व के 6 ट्रेनिंग पैकेजेज़ का निर्माण कर उपलब्ध कराए। वार्षिक पंचाग बना कर संस्थानों को उपलब्ध कराए गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, सी. आई. ई. टी. जोधपुर, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर एवं संस्थान द्वारा अकादमिक कार्यक्रमों में एकरूपता की दृष्टि से समन्वय एवं सहयोग का निर्णय लिया गया। 13 प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किए गए। बागड़ी हिन्दी प्रायोजना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रायोजना, अनुसूचित जाति एवं जन जाति एवं महिला शिक्षा की कार्य योजनाओं की क्रियान्विति सफलतापूर्वक की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान राज्य में माध्यमिक शिक्षा से संबंधित परीक्षाओं के आयोजन तथा शैक्षणिक उन्नयन संबंधी कार्य सम्पादित करता है तथा साथ ही माध्यमिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों एवं अध्यापकों के शैक्षिक उन्नयन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 1991-92 के विशिष्ट कार्यों की प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है—

पाठ्यक्रम

- आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम में संशोधन की सुनिश्चित व्यवस्था
- शिक्षाविदों एवं विषय विशेषज्ञों को पाठयक्रमों के निर्माण एवं संशोधन से जोड़ना।
- सहज पठनीय, रोचक एवं उपयोगी पाठ्यपुस्तकों का निर्माण।

परीक्षाओं का आयोजन

- बोर्ड की विश्वसनीयता एवं स्तरीयता को सुदृढ़ बनाने के प्रयास
- लगभग साढे तीन लाख परीक्षार्थी माध्यमिक स्तर पर एवं लगभग दो लाख परीक्षार्थी सी. उच्च माध्यमिक स्तर पर
- शिक्षा कलेण्डर का समयबद्ध क्रियान्वयन

मान्यता

- माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रवेशिका एवं उपाध्याय स्तर के 3999 विद्यालयों को मान्यता
- परीक्षा केन्द्र 1378

स्तरोन्नयन

- विषय अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम
- सन्दर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम
- अध्यापन प्रतियोगिताएं एवं सेमीनार रीडिंग
- प्रश्न-पत्र निर्माण एवं विश्लेषण
- पत्राचार पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम

सैकण्डरी स्तर का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के अनुरूप बनाया जाकर सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया गया है। +2 स्तर के अकादमिक धारा के पाठ्यक्रम को भी परिवर्तित/परिवर्द्धित किया जा चुका है तथा इसे कक्षा 11 में जुलाई 1991 से लागू किया जा चुका है। जुलाई 1992 से इसे कक्षा 12 में प्रारम्भ कर दिया जायेगा। इसी प्रकार +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा धारा के अन्तर्गत अब तक 21 पाठ्यक्रम लागू किये जा चुके हैं।

परीक्षा

बोर्ड द्वारा वर्ष 1991 में निम्नांकित परीक्षाएं आयोजित की गई तथा उनके सम्मुख लिखी गई संख्या में परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए–

1. सैकण्डरी स्कूल परीक्षा	3,47,323
2. प्रवेशिका परीक्षा	3,913
3. सीनियर सैकण्डरी (अकादमिक) परीक्षा	1,73,880
4. सीनियर सैकण्डरी (व्यावसायिक) परीक्षा	2,526
5. सीनियर उपाध्याय परीक्षा	1,405
	योग 5,29,047

मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या

वर्ष 1991 में बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या निम्नानुसार रही–

1. सैकण्डरी	2,979
2. सीनियर सैकण्डरी	899
3. प्रवेशिका	78
4. सीनियर उपाध्याय	43
	योग 3999

वर्ष 1991 की परीक्षाओं हेतु केन्द्रों की संख्या 1,378 रही

गुणात्मक उन्नयन

बोर्ड द्वारा परीक्षा प्रणाली में उद्देश्यनिष्ठता, पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण, अध्यापकों के व्यावसायिक स्तरोन्नयन, उनमें चिन्तन, सृजनात्मकता एवं प्रयोग की अभिवृत्तियों के विकास के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये गये।

अध्यापक उन्नयन

अध्यापकों के उन्नयन की दृष्टि से बोर्ड द्वारा 1991-92 में निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये–

प्रश्नपत्र कार्यगोष्ठियां–वर्ष 1991-92 में 13 विषयों की 4 कार्यगोष्ठियां आयोजित की गई जिसमें 93 अध्यापकों की प्रश्न पत्र निर्माण में प्रशिक्षित किया गया।

संदर्भ्य व्यक्ति प्रशिक्षण–बोर्ड द्वारा संदर्भित सत्र में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान लेखांकन विषयों की 8-8 दिनों की 4 कार्यगोष्ठियां आयोजित की गई जिसमें 147 विषयाध्यापकों को संदर्भ्य व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

एस.यू.पी.डब्ल्यू. के क्षेत्र में प्रशिक्षण–एस. यू. पी. डब्ल्यू. के क्षेत्र में संस्था प्रधानों के प्रशिक्षण हेतु दो कार्यगोष्ठियां आयोजित की गई जिसमें 77 संस्था प्रधानों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड द्वारा इस वर्ष प्रवृत्ति प्रभारियों के प्रशिक्षण के लिए पहली बार कार्यगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें 54 संभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। एस. यू. पी. डब्ल्यू. विषय की सर्वश्रेष्ठ क्रियान्विति करने वाले चयनित विद्यालयों को राज्य स्तर पर रुपये 5,000/- की राशि तथा जिला स्तर पर रुपये 1,000/- की प्रोत्साहित राशि प्रदान की जाती है। इस वर्ष यह समारोह दिनांक 10 फरवरी, 1992 को भीलवाड़ा में आयोजित कर राज्य स्तर पर 8 विद्यालय (5 छात्र, 3 छात्रा) तथा जिला स्तर पर 13 विद्यालयों को (5 छात्र व 8 छात्रा) पुरस्कृत किया गया।

अध्यापन प्रतियोगिता

इस वर्ष अध्यापन प्रतियोगिता हेतु बोर्ड द्वारा रुपये 4,300/- की राशि का अनुदान दिया गया।

सेमिनार रीडिंग

अध्यापकों के चिन्तन, प्रयोग एवं अभिव्यक्ति में सृजनशीलता के उत्प्रेरण हेतु सेमिनार रीडिंग आयोजित की गई। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले अध्यापकों को क्रमशः 500/-, 300/- एवं 200/ की राशि से पुरस्कृत किया गया।

प्रयोगों एवं प्रायोजनाओं के लिए अनुदान राशि

बोर्ड द्वारा सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को अपने विषय क्षेत्र में उन्नयन करने के लिए प्रोत्साहन हेतु रुपये 500/- तक की रांशि अनुदान दी जाती है तथा चयनित शोधकर्ता को इस हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया।

परीक्षा परिणाम का विश्लेषण

बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों का इस वर्ष भी विद्यालय वार, विषयवार, न्यून एवं उच्च परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यालयों का परीक्षा वार विश्लेषण करवाया गया। परीक्षा परिणाम में संख्यात्मक एवं गुणात्मक स्थिति का चित्र स्पष्ट किया गया, ताकि शिक्षा अधिकारी परीक्षा परिणाम के उन्नयन हेतु आवश्यक व्यवस्था कर सकें।

प्रश्न पत्र विश्लेषण

हर वर्ष की भांति वर्ष 1991-92 में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करवा कर प्रश्न पत्र निर्माताओं को उनके निष्कर्ष उपलब्ध करवाये गये ताकि प्रश्न पत्र का स्तर अच्छा किया जा सके।

छात्रों के लिए अधिगम सामग्री का निर्माण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 के अन्तर्गत सैकण्डरी स्तर पर लागू किये गये पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए सैकण्डरी स्तर के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न बैंक की स्थापना की गई। विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक तैयार करवा कर प्रकाशित किये जा चुके हैं।

व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत अब तक बागवानी एवं फसल उत्पादन विषयों में अधिगम सामग्री मुद्रित करवा कर छात्रों को उपलब्ध करा दी गई है। इसके साथ ही 8 विषयों में पाठ्य पुस्तक लेखन का कार्य कार्यगोष्ठी की पद्धति से चल रहा है।

प्रतिभाखोज परीक्षा

बोर्ड द्वारा 1991-92 में भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई जिसमें 3665 प्रतियोगियों ने परीक्षा दी। इसके साथ ही विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा भी आयोजित की गई, इसमें 3580 परीक्षार्थियों ने भाग लिया।

बोर्ड शिक्षण पत्रिका

1964 से बोर्ड एक द्वि-भाषीय त्रैमासिक शिक्षण पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है। इस पत्रिका के लगभग 18,000 रजिस्टर्ड ग्राहक हैं।

पत्राचार पाठ्यक्रम

वर्ष 1990-91 में पत्राचार पाठ्यक्रम योजना में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में कक्षा 12 स्तर पर कुल 47,572 छात्र नामांकित हुए थे। वर्ष 1991-92 में इस योजना के अन्तर्गत 24,112 छात्र नामांकित हुए हैं।

सैकण्डरी स्तर पर भी बोर्ड ओपन स्कूल स्थापित करने की योजना पर विचार कर रहा है ताकि इसके माध्यम से माध्यमिक स्तर पर भी अच्छी एवं स्तरीय शिक्षा ऐसे सभी छात्र/छात्राओं को उपलब्ध कराई जा सके जो कि किसी भी कारणवश शालीय शिक्षा से वंचित रह गये हैं या छोटे-मोटे धन्धों में कार्यरत रहकर अब शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं। ओपन स्कूल के माध्यम से छात्र/छात्राएं सैकण्डरी परीक्षा अपनी सुविधा से एक बार के स्थान पर 4-5 बार में टुकड़ों में विभिन्न विषयों की परीक्षा उत्तीर्ण कर सर्टिफिकेट प्राप्त करने का अवसर ले सकेंगे जिससे जो छात्र धन्धे में कार्यरत हैं वे धन्धों की जारी रख सकेंगे तथा पढ़ाई भी कर सकेंगे।

उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजकीय महाविद्यालयों के वित्तीय, प्रशासकीय एवं शैक्षणिक मामलों का नियंत्रण एवं कार्यकलापों की देखरेख करता है। वर्तमान में इस निदेशालय के नियंत्रण में 32 स्नातकोत्तर एवं 37 स्नातक स्तरीय महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं। 50 सहायता प्राप्त महाविद्यालय पर भी इसका आंशिक नियंत्रण रहता है।

उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति

उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति के परिणामस्वरुप राज्य के सभी विद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिये हैं।

सांख्यिकी विवरण

महाविद्यालयों का एवं उनमें नामांकन स्थिति का सांख्यिकी विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

महिला-शिक्षा

सरकारी क्षेत्र में 7 महिला महाविद्यालय तथा निजी क्षेत्र में 40 महिला महाविद्यालय कार्यरत हैं। निदेशालय में एक महिला प्रकोष्ठ कार्य कर रहा हैं। प्रतिभावान छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। 4 महिला महाविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्र चल रहे हैं।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र में उच्च शिक्षा

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 6 राजकीय महाविद्यालय स्थापित हैं। 21 राजकीय महाविद्यालयों में इन छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग कक्षाएं चलती हैं।

व्यावसायिक शिक्षा

24 राजकीय महाविद्यालयों में रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम चल रहे हैं जिनमें कम्प्यूटर साइंस, गारमेन्ट प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, प्रिंटिंग एंड ड्राइंग, स्टेनो टाईपिंग, टैक्सटाईल्स केमेस्ट्री आदि हैं।

शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक गतिविधियां

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु महाविद्यालायों में अध्ययन के अलावा योजना-मंच, खेलकूद, एन.सी.सी. स्काउटिंग, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि आयोजित की जाती है।

छात्रवृत्तियां

योग्य एवं निर्धन छात्रों की कई प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, विशेषकर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति, महिला छात्रवृत्ति आदि।

1991-92 की प्रगति

1. राजकीय महाविद्यालायों के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए 4681 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इनमें 400 लाख रुपये योजना मद में एवं शेष गैर योजना मद में है।
2. इस वर्ष 4 नये राजकीय महाविद्यालय खोले गए। 9 नये विषय विभिन्न राजकीय महाविद्यालायों में खोले गए जिनमें 3 विषय व्यवसायोन्मुखी हैं।
3. महाविद्यालायों में अध्ययन सुचारु रुप से चलाये जाने एवं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए 'आकस्मिक निरीक्षण कार्य प्रारंभ किये गये।
4. निदेशालय में एक एकेडमिक रिसर्च सेल गठित किया गया है।
5. महाविद्यालयों में 19 नये वर्ग (17 कला एवं 2 विज्ञान) खोले गये। व्याख्याताओं के 57 पद स्वीकृत किये गये एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों के 68 पद सृजित हुए।
6. महाविद्यालायों के विकास कार्यक्रमों के लिए 16.62 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति यू.जी.सी. द्वारा दिलवाई गई।

1992-93 की वार्षिक योजना

इस योजना का कुल आउट ले 450 लाख रुपये है जिसमें से 326.66 लाख रुपये कमिटेड तथा 123.34 लाख रुपये नई योजनाओं के लिए रखा गया है।

वर्ष 92-93 की नई योजना में मुख्य रुप से निम्न प्रावधान रखे गये हैं

1. निदेशालय प्रशासन का सुदृढ़ीकरण करना।
2. 10 नये विषय प्रारंभ करना।
3. राजकीय महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ में रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षा खोलना।
4. 3 महिला महाविद्यालयों (श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, भरतपुर) में महिला अध्ययन केन्द्र खोलना।
5. 3 महिला डिग्री महाविद्यालयों को (अलवर, कोटा, बीकानेर) स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करना।
6. छात्र कल्याणकारी योजनाओं जिनमें 40 शोध छात्रवृत्तियां देने एवं विज्ञान के विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण हेतु आर्थिक सहायता देना।
7. अध्यापक कल्याणकारी योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता देना।

आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97

इस योजना में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु 3200 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे विशाल तथा सबसे पुराना शिक्षण संस्थान है। अपनी बहुआयामी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए यह एशियाई उपमहाद्वीप में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। राजस्थान विश्वविद्यालय का स्वरूप बहुसंकायी रहा है जिसमें कला, विज्ञान, समाज विज्ञान, वाणिज्य, ललित कला, आयुर्वेद, संस्कृत, मेडिकल, शिक्षा आदि संकायों के विविध विषयों के अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था है। इस विश्वविद्यालय में चारो संघटक महाविद्यालयों सहित 45 शैक्षिक इकाइयाँ हैं, जिनमें लगभग 15 हजार छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा लगभग एक हजार शिक्षक अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। इस विश्वविद्यालय में छात्रों के बहुमुखी विकास के लिए अनेकानेक पाठ्येत्तर प्रवृत्तियाँ संचालित की जाती रही हैं। इनमें राष्ट्रीय सेवा योजना, प्रौढ़ शिक्षा तथा एन.सी.सी. जैसी प्रवृत्तियों के साथ-साथ खेलकूद की विभिन्न गतिविधियां संचालित होती हैं। विश्वविद्यालय में अध्ययन-अध्यापन निर्बाध गति से अनवरत चल रहा है तथा आगामी परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है।

वर्ष 1991-92 की प्रमुख उपलब्धियाँ

1. पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम इस सत्र से प्रारंभ हो गया है।
2. विश्वविद्यालय में शिक्षा संकाय के तहत एम. एड. भी प्रारंभ कर दिया गया है।
3. नाट्य कला का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय में इसी सत्र से प्रारंभ किया है।
4. छात्रों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में सायंकालीन विधि कालेज की स्थापना की गई है।
5. विश्वविद्यालय शिक्षकों तथा कर्मचारियों को पेंशन देने की योजना को कार्य रूप दे दिया गया है।
6. भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के आर्थिक सहयोग से 34 कमरों का आवासीय भवन जो कि कार्यशील महिलाओं के लिए है, इसी सत्र में तैयार हो जाने की संभावना है।
7. विश्वविद्यालय परिसर में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा स्थापित की गई है।
8. छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की पूर्ति के लिए 14 मार्च, 1992 को छात्र संघ के चुनाव कराये जाने की घोषणा करदी गई है।
9. विश्वविद्यालय के एकेडेमिक स्टाफ कालेज की ओर से पूरे वर्ष रिफ्रेशर एवं ओरियंटेशन पाठ्यक्रम

संचालित किये गये।

10. विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत वरिष्ठ तथा चयनित वेतन श्रृंखला प्रदान की गई।

11. राजस्थान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के शिक्षकों ने राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठियों व कार्यशालाओं में भाग लेकर कला, मानविकी, विज्ञान ललित कला इत्यादि विभिन्न विषयों से संबंधित शोधपूर्ण पत्र प्रस्तुत कर नवीन उद्‌भावनाओं को उजागर किया।

12. विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष भी उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए पी. एच. डी. की उपाधियाँ प्रदान की गई।

अजमेर विश्वविद्यालय, अजमेर

इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अगस्त, 1987 की राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम संख्या 38/87 के तहत हुई। विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 1988 में करीब 3 लाख 1989 में, 1,10,000 तथा 1990 में 1,14,371 परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित की गयी और समय पर परिणाम घोषित किये गये।

सत्र 1990-91 में विभिन्न संकायों के लिए आयोजित परीक्षाओं में 1,01,357 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए तथा परीक्षा परिणाम यथा समय घोषित किये गये।

इस समय विश्वविद्यालय से 4 स्वायत्तशासी महाविद्यालयों सहित 109 महाविद्यालय सम्बद्ध हैं, इसका कार्यक्षेत्र श्रीगंगानगर से झालावाड़ और करौली से जैसलमेर तक है। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय अपने विस्तृत कार्यक्षेत्र में दूरस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा के विकास में संलग्न है। सत्र 1990-91 से विश्वविद्यालय ने दस जमा दो जमा तीन योजना आरम्भ कर दी है। जिसके अन्तर्गत बी.ए/ बी.एस.सी./बी.कॉम, पार्ट-I, पार्ट II, पार्ट III सम्मिलित हैं।

प्रथम कुलपति का कार्यकाल पूरा होने के तदुपरान्त लगभग 16 महीनों तक कार्यकारी कुलपतियों की नियुक्ति के पश्चात् वर्तमान में नियमित कुलपति की नियुक्ति हुई है इनके अथक प्रयासों द्वारा विश्वविद्यालय प्रगतिशील है।

विश्वविद्यालय कार्यालय व शैक्षणिक विभागों के भवन निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय द्वारा घूघरा घाटी पर सरकार द्वारा आवंटित लगभग 256 बीघा भूमि पर चल रहा है। भवन निर्माण का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा संपादित किया जा रहा है। लगभग 6 करोड़ रु. का कार्य हो चुका है तथा 1500 बीघा अतिरिक्त भूमि के आवंटन व अधिग्रहण का कार्य भी प्रगति पर है। आगामी कुछ महीनों में विश्वविद्यालय कार्यालय का अपने निजी भवन में स्थानान्तरित होने की संभावना है।

विश्वविद्यालय द्वारा इतिहास, राजनीतिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, विषयों में सत्र 1990-91 से एम. फिल, की कक्षायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं।

विश्वविद्यालय ने सत्र 1991-92 में 22 अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं करवाई, 20 अंतर विश्वविद्यालय टीमों ने भाग लिया। अन्तर विश्वविद्यालय पश्चिमी क्षेत्र (West Zone) महिला बास्केटबाल का भी आयोजन किया गया। हमारे विश्वविद्यालय की टेबिल टेनिस टीम, महिला बास्केटबाल हॉकी खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में गयी। पश्चिमी क्षेत्र में ये टीमें तीसरे स्थान पर रहीं।

वर्तमान में विश्वविद्यालय में 258 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं।

विश्वविद्यालय में वर्तमान में लगभग 437 शोध छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। तथा लगभग 18 शोध छात्रों को पी. एच. डी. की उपाधि प्रदान की जा चुकी है।

मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

वार्षिक प्रगति विवरण वर्ष 1991-92

विश्वविद्यालय ग्रीष्मावकाश के पश्चात जुलाई 1991 से इस शिक्षा सत्र 1991-92 के लिए खुल गया था, तथा त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश यथासमय दे दिये गये किन्तु गत वर्ष आरक्षण आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाए विलम्ब से प्रारम्भ हुई तथा परीक्षा परिणाम भी विलम्ब सें घोषित हो पाये जिसके कारण द्वितीय एवं तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रवेश जनवरी 1992 तक सम्पन्न हुए हैं। फिर भी जिनके प्रवेश जुलाई अगस्त में हुए उनका पाठ्यक्रम 60 प्रतिशत समाप्त हो चुका है और आशा की जाती है कि इस सत्र की वार्षिक परीक्षाएं यथासमय पर अर्थात् अप्रेल से जुलाई 1992 तक समाप्त हो सकेंगी और आगामी शैक्षणिक सत्र भी जुलाई से प्रारम्भ कर सकेंगे।

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस विश्वविद्यालय ने राजस्थान सरकार के आदेशानुसार पी. एम. टी. एवं पी. टी. ई. टी. परीक्षाएं आयोजित कीं तथा परिणाम भी घोषित हो चुके हैं। इस वर्ष सर्वाधिक संख्या पी. टी. ई. टी. के छात्रों की रही जिसमें लगभग 72 हजार छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए।

वर्ष 1991-92 की वार्षिक आयोजना के अन्तर्गत 30 लाख रु. की राशि उपलब्ध कराई गई। प्रदत्त दायित्वों हेतु 26.65 लाख रुपये एवं नवीन मदों हेतु 3.35 लाख रुपये आवंटित किये गये एवं वार्षिक आयोजना भिन्न में भी राज्य सरकार ने इस वर्ष 457.40 लाख रुपये आवंटित किये हैं। वर्ष 1991-92 में निम्नांकित नये रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम आरम्भ किये गये:

1. Diploma in Banking Management at College of Commerce. Udaipur.
2. Degree Course in Physical Education at B.N.College, Udaipur.
3. Computer Science Course at S.B.P. Govt. College, Dungarpur.

वर्ष 1991-92 में एक नये डिग्री राजकीय महाविद्यालय, सलूम्बर को सम्बन्द्धता प्रदान की गई है।

निर्माण कार्य की दिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई है क्योंकि दोनो विश्वविद्यालायों (सुखाडिया विश्वविद्यालय एवं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय) की संपत्ति का विवाद अब तक चल रहा है एवं सम्पूर्ण निर्णय अभी तक नहीं हुआ है।

जोधपुर विश्वविद्यालय

राज्य सरकार ने वर्ष 1991-92 के लिए जोधपुर विश्वविद्यालय को शिक्षा एंव शोध विकास हेतु रुपये 122 लाख (एक करोड बाइस लाख रुपये) जिसमें सामान्य शिक्षा हेतु रुपये 80.00 लाख तथा तकनीकी शिक्षा हेतु रुपये 42.00 लाख उपलब्ध करवाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु आठवी योजना काल में रुपये 130 लाख निर्धारित किये हैं, जिसमें चालू वर्ष में रुपये 33.00 लाख व्यय करने का प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विकास हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आठवीं योजना काल में रुपये 77.00 लाख निर्धारित किये हैं जिसमें रुपये 11 लाख चालू वर्ष में व्यय करने का प्रावधान है।

रोजगार उन्मुख होने के नाते एवं समय की मांग को देखते हुए इस विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र से स्नातकोत्तर स्तर पर "मास्टर ऑफ टूरिज्म एजूकेशन" पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसी सत्र से स्नातकोत्तर स्तर पर इलेक्ट्रोनिक एवं स्नातक स्तर पर पत्रकारिता एवं अनुवाद के पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार में विचाराधीन है।

विश्वविद्यालय ने 11 प्राध्यापकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने के लिए अधिकृत किया।

विश्वविद्यालय ने वर्तमान होम साइन्स विभाग का संवर्धन कर बी. एस. सी. स्तर पर होम साइन्स में पृथक डिग्री देने का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। साथ ही साथ स्वयंपाठी विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न हुई एवं उनके परिणाम भी समयानुसार घोषित कर दिये गये।

राज्य सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए विश्वविद्यालय को रुपये 112.49 लाख (रुपये एक करोड बारह लाख उनचास हजार) की सीमा राशि व्यय हेतु आवंटित कर निर्धारित की है, जिसमें सामान्य शिक्षा हेतु रुपये 76.96 लाख (रुपये छियत्तर लाख छानवे हजार) तथा तकनीकी शिक्षा हेतु 35.53 लाख (पैंतीस लाख तरेपन हजार) की राशि व्यय हेतु निर्धारित की है।

कोटा खुला विश्वविद्यालय

कोटा खुला विश्वविद्यालय 23 जुलाई, 1987 को देश में खुले विश्वविद्यालय के कार्य के भाग के रूप में स्थापित किया गया था। यह विश्वविद्यालय सेवारत व्यक्तियों एवं घरेलू महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के द्वारा कैरियर के विकास हेतु उच्च शिक्षा प्रदान करने का अवसर देता है।

वर्ष 1991-92 के लिए योजना मद में रुपये 88.35 लाख विश्वविद्यालय भवन परियोजना निर्माण के लिए आवंटित किए गये हैं। राज. राज्य पुल निगम को एक निर्माण एजेन्सी के रूप में इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है। इसकी बाउण्ड्री का कार्य प्रायः पूर्णता पर है। प्रशासकीय खण्ड एवं 60 विभिन्न सेवा वर्गों के कर्मचारियों के क्वाटर्स के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

रूढ़िगत पत्राचार पाठ्यक्रम की प्रणाली को खुली प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत 8 विभिन्न पाठ्यक्रमों को चलाया जाता है। सामाजिक विज्ञानों एवं कला में अधिस्नातक पाठ्यक्रम तथा एम. एड. कार्यक्रम के अलावा भविष्य में बी. एस. सी. एवं फार्मेसी में डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये जाने का कार्यक्रम है।

इस विश्वविद्यालय के 6 क्षेत्रीय केन्द्र, 28 अध्ययन केन्द्र 8 कम्प्यूटर प्रेक्टिकल ट्रेनिंग सेन्टर, विद्यार्थियों को मल्टी मीडिया प्रणाली द्वारा दूरस्थ शिक्षा देने के लिए रखे गये हैं।

अध्ययन केन्द्रों का विस्तार राजस्थान के प्रत्येक जिले में करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के तहत इस विश्वविद्यालय का खाड़ी देशों में अध्ययन केन्द्र खोलने का मामला विचाराधीन है। नये विश्वविद्यालय केम्पस में दीर्घमात्रा में पौधे लगाये गये हैं।

इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने वर्ष 90-91 में केन्द्रीय सहायता के रूप में रुपये 22 लाख स्वीकृत किये हैं। कम्प्यूटर, हार्डवेयर के संस्थापन का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों की सामग्री प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों द्वारा तैयार की जाती है। इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में इसके बी. एड. एवं बी. जे. एम. सी. विद्यार्थियों द्वारा भाग लेना शुरु किया है। विद्यार्थियों को डिग्री देने में एक प्रौढ़ को शिक्षित किये जाने के प्रमाण पत्र जो संबंधित जिले के शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, के प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई है।

कोटा खुला विश्वविद्यालय एशियन एसोसिएशन ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, कोमन वेल्थ एसोसिएशन तथा इंडियन यूनिवर्सिटी एसोसिएशन का स्थाई सदस्य है।

संस्कृत शिक्षा

राष्ट्र की भावनात्मक एवं सांस्कृतिक एकता, अखण्डता तथा भाषाओं के विकास के लिए संस्कृत भाषा के अपूर्व योगदान को दृष्टिगत रखते हुए सदैव राज्य सरकार का यह प्रयत्न रहता है कि संस्कृत की दृष्टि से राजस्थान को जो गौरवपूर्ण स्थान देश में मिला हुआ है, वह न केवल कायम रहे, बल्कि संस्कृत शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान अन्य राज्यों के लिए आदर्श भी बने। अतः राज्य प्रशासन द्वारा संस्कृत शिक्षा के लिए स्वतंत्र विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना, उनका विकास तथा संस्कृत शिक्षण के विस्तार एवं प्रसार के कार्यक्रमों की अधिक शक्ति, चेतना और प्रतिबद्धता के साथ लागू किया जा रहा है।

1. आलोच्य वर्ष में संस्कृत शिक्षा सेवा के प्राचार्य/ प्रोफेसर आदि 9 पदों के वेतनमानों में सुधार किये गये।
2. वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1991-92 में विभिन्न स्तर की राजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में 67 संस्थाओं की वृद्धि हुई है। जिनमें 2 शास्त्री कालेज, 3 वरिष्ठ उपाध्याय, 3 प्रवेशिका, 19 उच्च प्राथमिक तथा 40 प्राथमिक विद्यालय है।
3. वर्ष 1990-91 में 1.80 लाख छात्र/छात्राएं 832 राजकीय-अराजकीय संस्कृत शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत थे। आलोच्य वर्ष में छात्रों की संख्या में 26.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। गत वर्ष के अनुसूचित जाति के 17 हजार तथा अनुसूचित जनजाति के 18 हजार छात्रों ने इस वर्ष क्रमशः 21.96 तथा 13.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों का संस्कृत के प्रति अधिक आकर्षण हुआ है-वहां इसे आदि-भाषा होने से अपनी भाषा मानकर प्राथमिकता से पढ़ा जाता है।
4. राज्य के 24 विद्यालयों में भवन की मरम्मत तथा भवन के निर्माण हेतु विभाग द्वारा 7.59 लाख रुपये तथा संस्कृत निदेशालय के भवन हेतु 10.00 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इस प्रकार वर्ष 1991-92 में संस्कृत शिक्षा में भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में कुल 17.59 लाख का आवंटन कराया गया है। इसके अतिरिक्त 30 जिले 30 काम तथा अल्पबचत योजना के अन्तर्गत संस्कृत विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण हेतु 18.03 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं।
5. संस्कृत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 5 प्रौढ़ पंडितों को राज्यस्तरीय संस्कृत दिवस समारोह के अवसर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
6. प्रौढ़ बोर्ड एवं विश्वविद्यालय स्तर पर संस्कृत के पाठ्यक्रमों का विकास किया गया है तथा शिक्षण संस्थाओं की फर्नीचर, अध्यापन, उपकरण व साज सामान हेतु 7.13 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है।
7. विद्यालयों में नई कक्षाओं के प्रारम्भ होने तथा विद्यालयों की क्रमोन्नति के फलस्वरुप 442 शैक्षणिक तथा 22 अशैक्षणिक नये पद स्वीकार किये गये।
8. वर्ष 1992-93 में नये कार्यों के लिए 11.98 लाख की राशि के अन्तर्गत 5 संभागीय कार्यालयों के लिए वाहन किराया, एक शास्त्री कालेज, एक वरिष्ठ उपाध्याय तथा जन जाति आयोजना में एक प्रवेशिका विद्यालय की क्रमोन्नति तथा शिक्षण संस्थाओं के भवनों की मरम्मत व विस्तार का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

एन. सी. सी. निदेशालय, राज. जयपुर

राष्ट्रीय केडिट कोर की स्थापना राजस्थान मे सन् 1949 में 200 केडिटों तथा 3 इकाईयों के साथ हुई। राजस्थान में एन. सी. सी. निदेशालय सन् 1963 में स्थापित किया गया था। उस समय 14 एन. सी. सी. इकाईयां थीं। उत्तरोत्तर विकास से अब राजस्थान के एक कोने से दूसरे कोने तक राष्ट्रीय केडिट कोर निदेशालय के अधीन चार ग्रुप मुख्यालय एवं 35 एन.सी.सी. इकाईयां हैं जिन पर प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय का है। इनमें छात्र इन्फैन्ट्री, बटालियन-8, छात्रा इन्फैन्ट्री बटालियन-4, वायु सेना इकाई-4, जल सेना इकाई-2, इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनी-6, टेक्निकल एवं अभियांत्रिक इकाईयां-11 हैं। राष्ट्रीय केडिट कोर कार्यक्रम में पहले केवल सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था, तथा अब सैनिक प्रशिक्षण के साथ-साथ खेलकूद, साहसिक प्रशिक्षण पर्वतारोहण, हवाई कूद, नौकायन अभियान, साईकिल अभियान तथा समाज सेवा आदि कार्यक्रम इसके प्रमुख अंग बन गये हैं।

एन. सी. सी. संगठन

इस संगठन में उप महानिदेशक एन.सी.सी. एयर कमांडर रेंक के हैं तथा चार ग्रुप मुख्यालयों पर कर्नल रेंक के ग्रुप कमाण्डर हैं। चारों ग्रुप कमाण्डरों के अधीन 35 एन.सी.सी. इकाईयां हैं। एन.सी.सी.इकाइयों पर आफिसर कमाण्डिंग लेफ्टिनेन्ट कर्नर रेंक के तथा कुल इकाई के मेजर रेंक के हैं. इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारी एडम आफिसर भी हैं। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन.सी.सी. निदेशालय में अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। जिनमें एक उप महानिदेशक एन.सी.सी. (एयर कमांडर) एक निदेशक कर्नल रेंक के होते हैं। एक संयुक्त निदेशक कार्मिक (ले.कर्नल) एक संयुक्त निदेशक/प्रशिक्षण विंग कमाण्डर/एक उप निदेशक समन्वय शाखा (मेजर) एक उप निदेशक एडम (मेजर) तथा एक लेखाधिकारी हैं। इन अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निदेशालय में एक अतिरिक्त निदेशक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के चयन वेतन श्रृंखला का अधिकारी एवं एक लेखाधिकारी राजस्थान लेखा सेवा का पद पदस्थापित है।

(2) वर्ष 91-92 में राजस्थान एन.सी.सी. सीनियर डिविजन केडिट्स की अधिकृत संख्या 14060 व जूनियर डिविजन में केडिट्स की अधिकृत संख्या 28350 है।

(3) जल, थल एवं वायु सेना संबंधी एन.सी.सी. प्रशिक्षण का वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में मूल्यांकन होता है, जिसमे साहसिक जीवन सामूहिक आवास सामाजिक सेवा प्रशिक्षण आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है।वर्ष 91-92 में निम्न शिविर सम्पन्न कराये गये हैं :—

सीनियर डिविजन	सम्पन्न शिविरों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
थल सेना	14	6995
जल सेना	2	170
वायु सेना	1	320
छात्रा सेना	2	510
जूनियर डिविजन		
थल सेना	19	8580
जल सेना	2	1500
वायु सेना	4	2130
छात्रा सेना	1	450

उपरोक्त वार्षिक शिविरों के अतिरिक्त महानिदेशक एन.सी.सी. नई दिल्ली द्वारा विभिन्न स्थानों पर निम्न शिविर आयोजित किये गये–

शिविरों के नाम	छात्र	छात्रा
केन्द्र द्वारा आयोजित शिविर	520	65
नौ सैनिक शिविर	45	–
वायु सैनिक शिविर	42	5
नेशनल इन्टीगेशन शिविर	694	625
अटेचमेन्ट		
आर्मी	308	–
एयर	15	–
नेवि	5	–
गर्ल्स	–	36

(4) सामाजिक कार्य

वर्ष 90-91 में एन.सी.सी. के छात्रों ने निम्नलिखित सामाजिक कार्य किये–

1. एन.सी.सी. केडिट्स द्वारा 34456 वृक्षारोपण किया गया।
2. 148 एन.सी.सी. केडिट्स ने रक्तदान किया।
3. 7500 केडिटस ने 1990-91 में दहेज प्रथा के विरुद्ध शपथ ग्रहण की।
4. प्रौढ़ शिक्षा प्रदान करने के लिए 1627 केडिटों ने भाग लिया एवं 1959 प्रौढ़ों को साक्षर किया।

(5) भविष्य की योजना

अब एनसीसी संगठन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। प्रथम बार पंचवर्षीय योजना में एनसीसी इकाईयों की वृद्धि के लिए 1 करोड़ 8 लाख (1.8) का व्यय किया गया था, जिसमे केडिटों की संख्या में बढ़ोतरी तथा साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण उपकरण उपलब्ध कराने पर व्यय किया गया था। इस वर्ष 1992-93 की वार्षिक योजना में आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण जैसे एयर मोडलिंग एवं शिप मोडलिंग इत्यादि क्रय करने का प्रावधान रखा गया है जिसमे 1600 छात्र/छात्राओं को आधुनिक प्रशिक्षण का लाभ हो सकेगा। इस पंचवर्षीय योजना में 1000 केडिटों की संख्या में वृद्धि व एक जैटी बोट का निर्माण एवं एक कार्यालय भवन का निर्माण कराने का लक्ष्य है। इस योजना में केडिटों की वृद्धि के साथ-साथ 10 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। एन.सी.सी. विभाग द्वारा अन्य कार्यक्रम जैसे वृक्षारोपण, रक्तदान, दहेज प्रथा, यातायात नियन्त्रण, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्यक्रमों में निःशुल्क योगदान दिये जाने का लक्ष्य है।

(6) वित्तीय आंकडे

राष्ट्रीय केडिट कोर के लिए भारतीय सुरक्षा विभाग के अतिरिक्त राज्य सरकार से वर्ष 1991-92 के लिये 334.49 लाख रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

(7) उपसंहार

साहस, शौर्य, अनुशासन और कर्तव्य का उद्घोष करते हुए देश की तरुनाई एन.सी.सी. केडिट के रूप में कर्त्तव्य पथ पर अग्रसर है। सन् 1949 से स्कूल व कालेजों में छात्र/छात्राओं के लिये प्रारम्भ इस योजना के कारण संबंधित छात्रों ने जहां अपने आपको अनुशासन पालन में समर्पित किया वहीं दूसरी ओर सृजनात्मक रचनात्मक सामाजिक कार्यों में भी उनका योगदान रहा है।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7272
Date........ 16-11-92

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड्

आर्थिक अनुदान

क्र. सं.	मद का नाम	वर्ष 91-92 में स्वीकृत	वर्ष 92-93 हेतु प्रावधान (प्रस्ताव)
1.	नान प्लान	39.25 लाख	48.10 लाख
2.	प्लान	8.00 लाख	10.00 लाख

प्रगति प्रतिवेदन

—कुल गणना 281500 वृद्धि 8 प्रतिशत।
—गुणात्मक वृद्धि 10 प्रतिशत
—गतिविधियों में सहभागिता 52550 स्काउट/गाइड् (गतिविधि संख्या 1020)
—समाज सेवा 592540 घण्टों की समाज सेवाएं विभिन्न कार्यों में की गई।

विशेष योजनाएं

क्र. सं.	नाम गतिविधि	संख्या गतिविधि	संभागी संख्या
1.	ग्रामीण रोवरिंग/रेंजरिंग	59	1290
2.	जनजाति स्काउटिंग	152	4885
3.	पर्यावरण संरक्षण व सुधार	16	800
4.	सेनीटेशन प्रमोशन	30	1200
5.	टीकाकरण कार्यक्रम—सभी जिलों में शिविरों का आयोजन कर विशेष चेतना जागृत की गई।		

मुख्यमंत्री शील्ड प्रतियोगिता कार्यक्रम

इस योजनान्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम सम्पन्न किये गये—

20000 वृक्ष लगाए गए, 19000 व्यक्तियों को साक्षर किया गया, अल्प बचत के 8000 खाते खुलवाए गए। 20000 वस्त्र एकत्र कर वितरित किए गए, 18000 विद्यालयों के विकास में योगदान दिया गया, 60 व्यक्तियों द्वारा रक्तदान किया गया, 35 ग्रामों में खेलकूद क्लबों को संचालन किया, 30 अभिरुचि केन्द्रों का संचालन किया गया।

प्लेटिनम जुबली वर्ष कार्यक्रम

संगठन ने इस वर्ष अपने 75 वर्ष पूरे किए हैं इसके आयोजन में सभी जिला मुख्यालायों पर युवा रैलियों का आयोजन, सम्मेलन व संगोष्ठियां की गई। जिसमें 20000 युवक/युवतियों ने सहभागिता की।

विशिष्ट अतिथि

दिनांक 17 जनवरी, 92 को विश्व स्काउट/गाइड् के चुने हुए 11 राष्ट्रों के प्रतिनिधि मण्डल ने अजमेर में आयोजित जनजाति रोवर/रेंजर व ग्रामीण हस्तकला एवं लघु उद्योग प्रतिभा शिविर का अवलोकन कर इसकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की।

भाषा विभाग

लोकहितकारी प्रशासन का माध्यम जनभाषा ही होनी चाहिए यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। इसके क्रियान्वयन हेतु राजस्थान ने राजस्थान राजभाषा अधिनियम 1956 द्वारा हिन्दी को राजभाषा स्वीकृत किया तथा प्रशासन, विधि, न्याय आदि सभी क्षेत्रों में हिन्दी को प्रतिष्ठापित करने के सक्रिय प्रयास शुरु किया। प्रशासन में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को पूर्णता प्रदान करने की दिशा में भाषा विभाग योजनाबद्ध तरीके से कार्यरत है। आलोच्य अवधि में इस दिशा में उठाये गये कदमों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

मुख्य बिन्दुओं पर एक दृष्टिपात

- मुख्यमंत्री/मंत्रियों को प्रस्तुत फाइलों में हिन्दी की अनिवार्यता
- विश्वविद्यालयों में हिन्दी प्रयोग का कार्यक्रम
- तीन राजभाषा प्रदर्शनियां : विभागों में हिन्दी दिवस समारोह
- तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी प्रयोग हेतु "उपकरण विशेषांक" तथा तकनीकी समिति
- राजस्थानी भाषा की मान्यता एवं संवर्धन हेतु उन्नयन समिति
- 900 पृष्ठों का अनुवाद : मैन्युअल्स हिन्दी में

हिन्दीकरण

मुख्य सचिव ने अपने अ. शा. पत्र दिनांक 8.2.91 द्वारा समस्त शासन सचिवों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों को फाइलों पर टिप्पणी हिन्दी में ही प्रस्तुत की जाय।

आलोच्य अवधि में दिनांक 30 अक्टूबर, 91 को संसदीय राजभाषा समिति के मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा एवं भाषा मंत्री ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में राजभाषा हिन्दी की प्रगति का विवरण दिया। जिस पर समिति ने यह अभिमत व्यक्त किया कि राजस्थान राजभाषा कार्यों में हिन्दी भाषी राज्यों में अग्रणी है।

भाषा एवं शिक्षा सचिव ने अपने अ.शा. पत्र दिनांक 9 जुलाई 91 द्वारा सभी अर्द्ध सरकारी संस्थानों से अनुरोध किया कि रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं औद्योगिक विकास बैंक से हिन्दी में ही पत्राचार किया जाए तथा अपने संस्थान के दैनिक कार्यों में हिन्दी प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों

में हिन्दी प्रयोग को पूर्णता प्रदान करवाने हेतु शिक्षा एवं भाषा सचिव ने अपने अ. शा. पत्र दिनांक 26.12.91 द्वारा विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के सिलेबस फार्म आदि मुद्रित सामग्री हिन्दी में जारी की जाए तथा प्रशासनिक कार्य भी हिन्दी में किया जाए। इस वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों का मुद्रण हिन्दी मे प्रारम्भ कर दिया है। अन्य विश्वविद्यालय भी इस पर कार्यवाही कर रहे हैं।

13 सितम्बर, 91 को राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में राज्य स्तरीय "हिन्दी दिवस समारोह" का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संपर्क हेतु भाषिक सेतु की तलाश विषयक संगोष्ठी आयोजित की गई।

राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस बार हिन्दी दिवस समारोह प्रदेश भर के विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विभिन्न विभागों में आयोजित किये गये एवं राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा की गई।

प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय जयपुर ने अपने कार्यालय आदेश दिनांक 23.9.91 द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अस्पतालों व कालेज में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारीगणों को निर्देश दिये कि वे समस्त कार्य हिन्दी में ही करें।

राज्य के स्वायत्त शासी संस्थानों, निगमों आदि की निर्देश दिये गये कि वे अपने समस्त कार्यों में हिन्दी का प्रयोग करें। हिन्दी प्रयोग का अभ्यास कराने के लिए अभिमुखीकरण कार्यशालाओं के आयोजन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की गई। विभिन्न विभागों एवं संस्थानों को हिन्दी के शुद्ध प्रयोग व वर्तनी के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

प्रकाशन

आलोच्य अवधि में कम्प्यूटर आदि यांत्रिक उपकरणों में हिन्दी की सुविधा को जानकारी देने हेतु विभागीय पत्रिका "भाषा परिचय" का उपकरण विशेषांक तथा राजस्थान की राजभाषा की संपूर्ण स्थिति दर्शाने वाला एक फोल्डर भाषा मंत्री ने प्रसारित किया।

राजभाषा प्रदर्शनियां

हिन्दी में राजकीय साहित्य, शब्दकोषों, तकनीकी पुस्तकों आदि की जानकारी के व्यापक प्रसारण के उद्देश्य से 3 प्रदर्शनियां लगाई गई, हिन्दी दिवस के अवसर पर राजभाषा प्रदर्शनी आयोजित की गई। दिनांक 14 नवम्बर 91 को राधाकृष्णन सार्वजनिक पुस्तकालय में शिक्षा विभाग एवं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी में विभाग ने "राजभाषा हिन्दी के बढ़ते कदम" नामक प्रदर्शनी लगाई।

सतर्कता अनुभाग

हिन्दी समाचार पत्रों में अंग्रेजी निविदा, विज्ञापन, नोटिस आदि प्रकाशित करवाने वाले कार्यालयों व उनके प्रशासनिक विभागों को यह अनुभाग तुरन्त ध्यानाकर्षण के पत्र भेजता रहता है। आलोच्य अवधि में हिन्दी प्रयोग के आदेशों की अवहेलना करने वाले विभिन्न विभागों को उचित निर्देश दिये गये।

राजभाषा क्रियान्वयन एवं तकनीकी समितियाँ

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने व उसकी देखरेख हेतु विभिन्न विभागों में राजभाषा क्रियान्वयन समितियां कार्यरत हैं। आलोच्य अवधि में सहकारी विभाग ने भी अपने यहां इस प्रकार की समिति का गठन किया।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा दिनांक 9 अप्रेल, 91 द्वारा तकनीकी विभागों के तकनीकी व अर्द्ध तकनीकी कार्यों के हिन्दी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी समिति का पुनर्गठन किया।

राजस्थानी भाषा का उन्नयन

कार्मिक विभाग की आज्ञा दिनांक 21 सितम्बर, 91 द्वारा राजस्थानी भाषा के उन्नयन एवं इसे आठवीं सूची में शामिल किये जाने हेतु परामर्श देने के लिए जो समिति गठित की गई है उसके सदस्य सचिव के रुप में निदेशक भाषा विभाग को मनोनीत किया गया है। उक्त समिति की बैठक 13 फरवरी 1992 की आयोजित की एवं महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

अनुवाद

अंग्रेजी की तकनीकी प्रशासनिक सामग्री का हिन्दी अनुवाद करना इस विभाग की एक प्रमुख योजना है। आलोच्य अवधि में 900 पृष्ठों का हिन्दी अनुवाद कर विभिन्न विभागों को भेजा गया। इस सामग्री में कुछ उल्लेखनीय पुस्तकें हैं—राजस्थान में पर्यटन विकास पर तैयार की गई दीर्घकालीन नीति की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री के भाषण, राजस्थानी आबकारी मैन्युअल, राजस्थान विश्वविद्यालय पेंशन प्रपत्रों का अनुवाद आदि।

हिन्दी शीघ्रलिपि प्रशिक्षण

राज्य सेवकों को हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण देने की योजना के अन्तर्गत आलोच्य अवधि में 50 कार्मिकों को हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण दिया गया। अब तक कुल 2635 व्यक्तियों की हिन्दी शीघ्रलिपि का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

शोध संदर्भ पुस्तकालय

आलोच्य अवधि में 50 संदर्भ ग्रन्थ शोध पुस्तकालय में नये आये। गजटों की 12 फाइलें व हिन्दी समाचार पत्रों की कतरनों की 12 फाइलें संधारित की गई। विभागीय शोध संदर्भ पुस्तकालयों में 8091 पुस्तकें, 20 पत्र-पत्रिकाएं, 7 समाचार पत्र भी संधारित हैं।

अनुदान

राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार व हिन्दी शीघ्रलिपि व हिन्दी टंकण का ज्ञान कराने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की 30,000 रु. की राशि का अनुदान प्रतिवर्ष दिया जाता है। आलोच्य अवधि में सिन्ध राष्ट्रभाषा प्रचार समिति व भारतीय हिन्दी संस्था को दो-दो हजार रुपए का अनुदान दिया जा चुका है। शेष आवेदनों की संवीक्षा की जा रही है।

राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर

राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की स्थापना दिनांक 28 जनवरी, 1988 को राज्य सरकार द्वारा राज्य के साहित्यिक विकास एवं उसके चहुँमुखी विकास के लिये की गई। राज्य सरकार द्वारा नवम्बर, 1962 में स्वायत्ता प्रदान की गई।

अकादमी की प्रमुख प्रवृत्ति राजस्थान के श्रेष्ठ व स्तरीय साहित्य का प्रकाशन करना है। इस योजना के अन्तर्गत अकादमी ने इस वर्ष 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया है। इसके अतिरिक्त अकादमी अखिल भारतीय स्तर पर "मधुमति" नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी कर रही है। अकादमी ने राजस्थान के प्रबुद्ध साहित्यकारों के कृतित्व व उनके साहित्यिक योगदान की सामान्य जन तक पहुँचाने का प्रयास किया है। इस योजना के अन्तर्गत 62 साहित्यकारों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इस वर्ष में प्रकाशित मोनोग्राम 4 है। इस वित्तीय सत्र 1991-92 में कुल 23 पांडुलिपियों पर 72 हजार रुपये का आर्थिक सहयोग पांडुलिपियों के प्रकाशनार्थ दिया गया है। सत्र सन् 1991-92 में लेखकों के निजी व्यय से प्रकाशित 6 ग्रन्थों पर कुल 19,500 रुपये का सहयोग दिया है। साहित्यिक पत्रिका के प्रकाशन में आर्थिक सहयोग योजना सत्र 1991-92 में 6 पत्रिकाओं की 1200/- रुपये का सहयोग दिया है। अकादमी ने राजस्थान की साहित्यिक संस्था को प्रसारात्मक कार्यक्रम की योजना हेतु 21 संस्थाओं को 29 हजार रुपये का सहयोग स्वीकृत किया है। सत्र सन् 1991-92 मे अकादमी द्वारा सक्रिय व संरक्षित समान सहयोग योजना के अन्तर्गत 7 साहित्यकारों की 22 हजार रुपये का सहयोग दिया गया। इसी प्रकार प्रान्त के रुग्ण व अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे साहित्यकारों की 8 हजार 250 रुपये की सहायता प्रदान की। अकादमी ने इसवर्ष आंचलिक रचनाकारो का समारोह सिरोही, नोहर, झुंझुनू व बारां युवा शिविर—जोधपुर, उदयपुर, लेखिका सम्मेलन जयपुर, साहित्यकार सम्मान समारोह व लेखक सम्मेलन कोटा में संपादित किये गये।

पाठक मंच

अकादमी राज्य में साहित्यिक चेतना जागृत करना, साहित्यिक वातावरण निर्माण करने और साहित्यिक ग्रन्थों के अध्ययन में अभिरुचि प्रदान करने के निमित पाठक मंच का आयोजन करते हैं। अकादमी द्वारा सत्र 1991-92 में 25 स्थानों पर पाठक मंच योजना के अंतर्गत गोष्ठियां आयोजित की। इसके अतिरिक्त सत्र 1991-92 में 15 व्यक्तियों की विभिन्न घोषित पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।

अकादमी ने इसवर्ष आयोजित विश्व पुस्तक मेले में भागीदारी की और अपनी स्टाल लगाई। इसके साथ ही अकादमी ने विभिन्न समारोहों के अवसर पर तथा स्वतंत्र रुप से अपने प्रकाशनों, साहित्यिक गतिविधियों की प्रदर्शनी भी आयोजित की।

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर

राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जुलाई 1991 में अपनी स्थापना के 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। अकादमी का उद्देश्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार उत्कृष्ट मानक एवं कम मूल्य पर पुस्तकों का प्रकाशन करना है ताकि उच्च शिक्षा के केन्द्रों में अध्ययन-अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी से हिन्दी में सुगमता से परिवर्तित हो सके।

पुस्तक प्रकाशन

अकादमी ने अब तक 361 पुस्तकों का प्रकाशन किया हैं तथा अकादमी वर्तमान में लगभग 280 पुस्तकों का लेखन कार्य करवा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रकाशकों द्वारा पिछले कुछ दशकों से अनेक विषयों में हिन्दी माध्यम की पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, किन्तु कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें हिन्दी माध्यम की पुस्तकें हैं ही नहीं या वे स्तरीय नहीं है। अतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी से होने वाले, माध्यम परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए अकादमी विज्ञान, आयुर्विज्ञान, गृह विज्ञान, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर, ललितकला, लेखा अंकेक्षण, बैंकिंग आदि पुस्तकों के निर्माण एवं प्रकाशन को प्राथमिकता दे रही है। अकादमी वर्ष 1991-92 में 14 पुस्तको को प्रकाशित कर रही है।

अकादमी ने सर्वाधिक प्रगति बिक्री क्षेत्र में की है। पिछले वर्ष अकादमी ने 12.60 लाख रुपये की पुस्तकों की बिक्री की तथा चालू वर्ष में 9.00 लाख रुपये की पुस्तकों की बिक्री हुई है।

राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर

अकादमी की प्रमुख प्रवृत्तियां, संस्कृत को सामान्य जनमानस में लोकप्रिय बनाने, संस्कृत के मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने, राजस्थान में उपलब्ध संस्कृत साहित्य की प्रकाशित करने तथा नवोदित प्रतिभाओं को प्रकाश में लाने से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अकादमी द्वारा 3 प्रवृत्तियों का संचालन किया जाता है—

1—अकादमी का स्वंय का प्रकाशन

2—सृजनशील साहित्यकारों को आर्थिक योगदान

3—त्रैमासिक संस्कृत पत्रिका में शोध व प्रवेशणात्मक
निबन्धों का प्रकाशन

अकादमी ने स्वयं प्रकाशन के रूप में 17 प्रकाशन जन-साधारण में प्रस्तुत कर दिये हैं। इस वर्ष 5 ग्रन्थों का प्रकाशन किया गया है। इस तरह राजस्थान की सांस्कृतिक परंपराओं पर 4 भागों में प्राचीन ग्रन्थों का प्रकाशन किया जा चुका है। स्वरमंगला पत्रिका के माध्यम से सस्ती दर पर इन गणेशात्मक निबन्धों का परिचय प्रस्तुत किया जाता है। सृजनकारा साहित्यकारों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस वर्ष इस योजना में 7 पुस्तकों को आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया है।

वेद संरक्षण योजना

संस्कृत के साथ-साथ वैदिक परंपराओं का परिचय भी जनसाधारण को करवाया जाता है। वेद पाठशालाओं का आश्रम पद्धति के आधार पर संचालन किया जाता हैं। यह भारत सरकार के सौजन्य से कार्यक्रम चल रहा है। वर्तमान में 9 वैदिक विद्यालयों का संचालन विभिन्न अंचलों में किया जा रहा है। इन विद्यालयों में 135 छात्रों द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 100 छात्रों की स्वर सहित यजुर्वेद संहिता का अध्ययन करवाया जाकर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जा चुका है।

वेद सम्मेलन

अकादमी के अधीन चल रहे वैदिक विद्यालयों के छात्रों का सम्मेलन इस वर्ष से प्रारंभ हुआ है। यह आयोजन निम्बकाचार्य पीठ सलेमाबाद में आयोजित किया गया था।

वैदिक सम्मेलन व प्रांतीय विद्वानों को संगठित कर जनता के सामने विभिन्न शैलियों का परिचय करवाया जाता है जो कि उपेक्षित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्तमान में यह आयोजन नाथद्वारा में आयोजित हो रहा हैं। इस वर्ष वेद भाष्कर संगोष्ठी का आयोजन अखिल भारतीय स्तर पर नाथद्वारा में सम्पन्न किया जा चुका है।

जयन्तियां

इस वर्ष कालिदास, माघ, मधूसूदन ओझा, जयन्तियों का आयोजन किया गया।

पुरस्कार

अकादमी द्वारा विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार इस प्रकार हैं—

(1) माघ पुरस्कार	6,000/- रुपये
(2) आचार्य नवल किशोर कांकर (वेद वेदांग पुरस्कार)	6,000/- रुपये
(3) पन्नालाल जोशी पुरस्कार	1,100/- रुपये
(4) बिहारी लाल पुरस्कार	1,100/- रुपये

(5) भारती मिश्रा पुरस्कार 1,100/- रुपये

(6) पं. अम्बिकादत्त व्यास पुरस्कार 500/- रुपये

(7) पं. मधुसूदन ओझा पुरस्कार 1,100/- रुपये

ये पुरस्कार विभिन्न प्रवृत्तियों पर देय होते हैं। इसी प्रकार महाविद्यालय और विद्यालय स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें सफल नवोदित प्रतिभाओं को अकादमी के वार्षिकोत्सव में सम्मानित किया जाता है।

राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी

राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना 19 जनवरी, 1986 को राज्य सरकार ने बृज साहित्यिक विकास और साहित्यिक संचेतना के प्रचार तथा साहित्यकारों के प्रोत्साहन और सहयोग से निर्मित की है। वर्ष 1991-92 में अकादमी द्वारा निम्न गतिविधियां सम्पन्न की गई हैं—

1. प्रकाशन (अ) पत्रिका ब्रजशतदल त्रैमासिक के 4 अंक

(ब) ब्रज साहित्यकार परिचय पोथी (मोनोग्राम) 4

(स) एक ग्रन्थ प्रकाशित तथा 3 प्रकाशनाधीन

समारोह (अ) ब्रज साहित्यकार सम्मान समारोह 14 दिसम्बर, 91 को नाथद्वारा में हुआ इसमें 5 साहित्यकारों का सम्मान किया गया।

(ब) ब्रज त्रिवेणी 18.1.92 को ब्यावर में हुआ।

(स) आंचलिक समारोह 7-8 फरवरी को डीग में हुआ।

(द) 22-23 फरवरी को अंतर प्रांतीय साहित्यकार बन्धुत्व यात्रा गोवर्धन (मथुरा में आयोज्य)

(र) 24.2.92 को नाथद्वारा में समारोह आयोज्य।

(स) 25.2.92 को कांकरोली में पढन्त समारोह आयोज्य।

उपरोक्त के अतिरिक्त होली पर जयपुर जोधपुर व बीकानेर में अखिल भारतीय ब्रजभाषा कवि सम्मेलन आयोज्य है, कामां में रचना शिविर, जयपुर में उपनिषद् समारोह, धौलपुर, भरतपुर, भुसावर में समारोह प्रस्तावित हैं। अकादमी द्वारा समारोह व प्रकाशनों के माध्यम से शोध परक समारोह होने हैं। अकादमी द्वारा समारोह व प्रकाशनों के माध्यम से शोध परक सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है तथा नए-नए साहित्यकारों को प्रोत्साहन देकर ब्रज साहित्य के प्रचार-प्रसार का कार्य करवाया जाता है।

राजस्थान की उर्दू अकादमी

अकादमी की जनरल कौंसिल द्वारा स्वीकृत बजट के अनुसार राजस्थान में उर्दू भाषा एवं साहित्य के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में सत्र 1991-92 में निम्न कार्य किया गया।

साहित्यकारों का सम्मान

अकादमी द्वारा राजस्थान के चार प्रसिद्ध साहित्यकारों को एक साथ पुरस्कार दिया गया, उनमें एक की 5,000/- का , तीन को 3,000/- रुपये का पुरस्कार दिया गया।

प्रकाशित पुस्तकों पर पुरस्कार

राजस्थान के तीन साहित्यकारों को उनकी प्रकाशित पुस्तकों पर 2,000/- रु. प्रत्येक की पुरस्कार स्वरुप दिये गये।

वजाइफ

राजस्थान के 26 शायरों और अदीबों को वजीफे और दस बीमार शायरों और अदीबों को ईलाज के लिए आर्थिक सहायता दी गई, तथा शायरों और अदीबों की 12 विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

अदबी अंजुमनों को माली इमदाद

अकादमी द्वारा निम्बाहेडा, बांसवाडा की अदबी संस्थाओं को 10,000/- व राजकीय महाविद्यालय, अजमेर को साहित्यिक समारोह के लिए 8,000/- रुपये आर्थिक सहायता दी गई।

समारोह

अखिल भारतीय उर्दू कन्वेन्शन : अंजुमन तरक्की ए-उर्दू (हिन्द राजस्थान उर्दू अकादमी की आर्थिक सहायता व तत्वावधान में 3 से 5 फरवरी, 92 को एक अखिल भारतीय उर्दू कन्वेन्शन आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस सेमीनार में राजस्थान के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, व दिल्ली के उर्दू विद्वानों ने भाग लिया। सेमीनार के विषय—राष्ट्रीय एकता का विकास, उर्दू भाषा को रोजागार से जोड़ने व भक्ति व तसव्वुफ जैसे अद्‌भुद विचारों पर आधारित थे।

इनामी मुकाबले

अखिल राजस्थान निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त जयपुर नगर के स्कूली बच्चों के सुलेख प्रतियोगिता, मुशायरे व किताबात प्रतियोगिता आयोजित की गई और इनको पुरस्कृत किया गया।

शैक्षणिक योग्यता

विश्वविद्यालय स्तर से लेकर प्राथमिक स्तर के उन विद्यार्थियों की जो उर्दू विषय में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये, उनको वज़ीफे दिये गये एवं पुरस्कृत किया गया।

निःशुल्क पुस्तकों का वितरण

प्रथम कक्षा से 8 वीं कक्षा तक निर्धन बच्चों के लिये स्कूल के माध्यम से इस वर्ष 20 स्कूलों की उर्दू की पाठ्यपुस्तकें 'उर्दू रीडर" निःशुल्क वितरित किये गये। जयपुर, झुंझुनूं, बीकानेर एवं मकराना में 5 रात्रिकालीन उर्दू टीचिंग सेन्टर अकादमी द्वारा चलाये जा रहे हैं।

प्रकाशन

उर्दू का त्रैमासिक जरीदा "नखलिस्तान" के इस वर्ष भी 3 अंक प्रकाशित हो चुके हैं। अकादमी द्वारा उर्दू साहित्यकारों की 3 पुस्तकों को इस वर्ष प्रकाशित किया गया है। लेखकों को प्रकाशन हेतु अकादमी ने आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की है।

राजस्थान सिन्धी अकादमी

वर्ष 1991-92 में अकादमी के तत्वावधान में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया गया। इस वर्ष सिंधी युवक-युवतियों एवं प्रौढ़ों को अपनी मातृभाषा सिंधी का ज्ञान उपलब्ध करवाने हेतु 100 रात्रिकालीन पाठशालाएं खोले जाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार राज्य के विभिन्न नगरों यथा टौंक, शाहपुरा, जोधपुर, बीकानेर जयपुर आदि में रात्रिकालीन शालाएं प्रारंभ कर दी गई हैं।

इस वर्ष राज्य स्तरीय 3 दिवसीय सिंधी एकांकी प्रतियोगिताओं का आयोजन भी उदयपुर में किया गया। इस प्रतियोगिता में राज्य की 8 नाटक मण्डलियों ने भाग लिया तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्रियों को नकद पुरस्कार प्रदान किये।

गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जोधपुर में सिन्धी कल्चरल सोसायटी के सौजन्य से जोधपुर नगर में सर्वभाषा कविगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस वर्ष कोटा सिंधी जनरल पंचायत के सहयोग सें कोटा में 2 दिवसीय राजस्थानी सिंधी अध्यापक सेंमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में राजस्थान के विभिन्न नगरों से लगभग 200 अध्यापक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सेमीनार में सिन्धी अध्यापकों ने संकल्प दोहराया कि वे सिन्धी भाषा की बढ़ाने के लिए लगन एवं मेहनत सें तथा निःस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे। समारोह में अकादमी की वार्षिक पत्रिका 'रिहाण' एवं मासिक समाचार बुलेटिन 'सिन्धू-दूत' के नये अंक का विमोचन भी किया गया।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राज्य के 11 सिन्धी साहित्यकारों को अपनी अप्रकाशित रचनाओं के प्रकाशन हेतु रुपये 3,000/- प्रति पुस्तक वित्तीय अनुदान दिया गया। इस वर्ष भीलवाड़ा में दो दिवसीय अखिल राजस्थान सिन्धी साहित्यकार सेमीनार एवं अखिल भारत कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 में कुल 40,000 विद्यार्थियों के नामांकन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आवंटित किया गया था जिसका बजट प्रावधान फलस्वरुप 7:5 के अनुपात में भारत सरकार से 51.,23,000/- रुपये स्वीकृत किये गये। जिसके प्रथम किश्त के रूप में 27,12,000/ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने कुल इसी अनुपात में 36.66 लाख रुपये स्वीकृत करने थे इसके विरुद्ध कुल 32.28 लाख ही स्वीकृत किये इस कारण 40 हजार छात्रों के नामांकन के विरुद्ध केवल 35 हजार छात्रों की ही नामांकित किया गया।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक छात्र की नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत 120 घण्टे सामुदायिक सेवाओं को पूरा करना होता है तथा एक 10 दिवसीय शिविर ग्रामीण अंचल में आयोजित करना होता है जिससे कि छात्र विभिन्न सामुदायिक विकास कार्य करते हुए साक्षरता कार्य, श्रमदान व सार्वजनिक कार्य करते हैं।

इस वर्ष चूंकि 16 हजार छात्रों को साक्षरता कार्यक्रम में लगाया जाना सुनिश्चित किया गया था इस हेतु छात्रों सें नेतृत्व क्षमता के विकास के लिये तथा साक्षरता अभियान को सफल रूप से संचालन करने के लिये आखरदान प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की सफल क्रियान्विति के लिए प्राचार्य/कार्यक्रम अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राजस्थान के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों/कार्यक्रम अधिकारियों की एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित किये जाने का निश्चय किया गया है जिससे वर्ष 92-93 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की सुदृढ़ नीति का निर्धारित हो सके।

राजस्थान राज्य पाठ्य-पुस्तक मण्डल

राजस्थान राज्य के अविभक्त इकाई (शिशु श्रेणी) के कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को बिना लाभ-हानि के आधार पर पाठ्य-पुस्तकों को समय पर सुलभ करवाने के उद्देश्य से फरवरी, 1965 मे शिक्षा विभाग राजस्थान के तत्वावधान में राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक मण्डल की स्थापना की गई थी। मण्डल को फरवरी, 1974 में स्वायत्तशासी संस्था का रूप दिया गया।

पुस्तक प्रकाशन एवं बिक्री

इस कार्यक्रम के तहत 44 शीर्षकों का प्रकाशन करवाया गया। इसवर्ष ट्रक आपरेटर्स की हडताल, उत्तर प्रदेश व पंजाब में कर्फ्यू व बन्द, चुनाव आदि से मुद्रण कार्य में काफी व्यवधान आया। किन्तु समस्त पुस्तकें शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व बाजार में उपलब्ध करवाई गई।

नये प्रयोग एवं उपलब्धियाँ

जयपुर शहर में मोबाईल पुस्तक वितरण केन्द्र चलाये गये, इससे पुस्तकें अधिकांश छात्रों को शालाद्वार पर ही उपलब्ध हो सकीं। साथ में चल पुस्तक वाहन से भी पुस्तकें ग्राहकों को उपलब्ध करवाई गई।

अनार्थिक डिपोज़ को बन्द करना

फुलेरा, डीग, खेड़ली, बिलाड़ा, शाहपुरा एवं बहरोड़ डिपोज पर 15 प्रतिशत से ज्यादा व्यय हो रहा था। इसे अनार्थिक मानते हुए बन्द कर मुख्य डिपोज में इनका विलय किया गया तथा ब्यावर डिपो को सहकारी सेक्टर में दिया गया।

मुद्रण कार्यक्रम 1992

मुद्रण कार्यक्रम में 43 शीर्षकों का प्रकाशन करवाया जाना है जिसके लिए मुद्रण आदेश दे दिये गये हैं तथा हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन एवं स्टार पेपर मिल्स से कागज भी क्रय कर लिया गया है। इस मुद्रण कार्यक्रम में निम्नलिखित पुस्तकों को परावर्तित किया जा रहा है–

1. हिन्दी – गणित	कक्षा – 2
2. गणित	कक्षा – 4
3. हिन्दी	कक्षा – 6
4. अंग्रेजी	कक्षा – 7

मुद्रकों ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है तथा कुछ पुस्तकों की आपूर्ति भी प्रारंभ हो गई है। आशा है अप्रेल-मई 92 तक समस्त पुस्तकों की आपूर्ति भी हो जायेगी। शिक्षा सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्त पुस्तकें उपलब्ध हो सकेंगी।

नये प्रयोग

1. मण्डल ने तय किया है कि गत सीजन में मोबाइल वितरण केन्द्र में काफी सफलता मिली थी, इसको ध्यान में रखते हुए अगले शिक्षण सत्र के प्रारम्भ होने पर इसका विस्तार किया जावेगा ताकि छात्रों और अभिभावकों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध हो सकें।

2. मुद्रण स्तर में सुधार लाने के लिए पुस्तकें/मण्डल स्तर पर कंपोज करवाई गई हैं। इससे मुद्रण स्तर में सुधार आ सकेगा तथा मुद्रण के लिये दिये जाने वाले समय में भी कमी की जा सकेगी। आने वाले वर्षों में मण्डल स्तर पर ही निगेटिव/पोजेटिव बनाये जाने की योजना है।

3. इस अवधि में मण्डल में आर्थिक व्यय में कटौती करने के उद्देश्य से 36 पदों में कमी कर दी गई है व 7 डिपोज को बन्द कर दिया गया है। मार्च 1990 के पश्चात् भारत सरकार द्वारा रियायती दर का कागज बन्द कर दिये जाने के कारण सरकार द्वारा सारा कागज खुले बाजार से क्रय किया जा रहा है। पूर्व में रियायती दर से प्राप्त कागज से चेतक अभ्यास पुस्तिकायें तैयार करवाई जाकर छात्रों को वितरित करवाई जाती थी किन्तु रियायती दर कागज बन्द होने के कारण इन कापियों का निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है।

विद्यालयी शिक्षा महत्वपूर्ण शैक्षिक आंकड़े, 1991-92

क्र.सं.	विवरण	उपलब्धियाँ
1	2	3
	अ. शिक्षण संस्थानों की संख्या	
1.	*पूर्व प्राथमिक विद्यालय*	
	बालक	14
	बालिकाएँ	19
	योग	33
2.	*प्राथमिक विद्यालय*	
	बालक	29508
	बालिकाएँ	2003
	योग	31511
3.	*उच्च प्राथमिक विद्यालय*	
	बालक	7640
	बालिकाएँ	1055
	योग	8695
4.	*माध्यमिक विद्यालय*	
	बालक	2660
	बालिकाएँ	455
	योग	3115
5.	*उच्च माध्यमिक विद्यालय*	
	बालक	796
	बालिकाएँ	190
	योग	986

6.	***महाविद्यालय***	
	पुरुष	122
	महिलाएँ	44
	योग	166
7.	***विश्वविद्यालय***	***6***
8.	***डीम्ड विश्वविद्यालय***	***3***
9.	***इंजिनियरिंग महाविद्यालय***	***6***
10.	***पोलिटेकनिक***	
	पुरुष	16
	महिलाएँ	5
	योग	21
11.	***औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान***	
	पुरुष	138
	महिलाएँ	5
	योग	143
12.	***शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय***	
	उच्च अध्ययन संस्थान	02
	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	01
	बी. एड.	36
13.	***शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय***	
	जिला शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान	27
	सीनियर टीचर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम	13
14.	***नवोदय विद्यालय***	***20***
15.	***प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र***	
	स्वीकृत	14350
	कार्यरत	6756
16.	***अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र***	
	स्वीकृत	11362
	कार्यरत	9829

शिक्षकों की संख्या

1. पूर्व प्राथमिक विद्यालय	
पुरुष	85
महिला	346
योग	431
2. प्राथमिक विद्यालय	
पुरुष	55440
महिला	18786
योग	74208
3. उच्च प्राथमिक विद्यालय	
पुरुष	52897
महिला	17456
योग	70353
4. माध्यमिक विद्यालय	
पुरुष	25988
महिला	6727
योग	32715
5. उच्च माध्यमिक विद्यालय	
पुरुष	22413
महिला	6994
योग	29407
6. उच्च शिक्षा (सामान्य)	
पुरुष	3334
महिला	1344
योग	4678

नामांकन	लाखों में
1. प्राथमिक शिक्षा (6-11 आयुवर्ग)	
बालक	35.79
बालिका	16.71
योग	52.50

2. *उच्च प्राथमिक शिक्षा (11-14 आयुवर्ग)*	
बालक	12.50
बालिका	4.12
योग	16.62
3. *माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षा (14-17)*	
बालक	5.09
बालिका	1.34
योग	6.43
4. *उच्च शिक्षा*	
बालक	1.34
बालिका	0.39
योग	1.73
5. *अनौपचारिक शिक्षा (6-14 आयुवर्ग)*	
बालक	1.32
बालिका	1.71
योग	3.03
6. *प्रौढ़ शिक्षा*	
बालक	1.00
बालिका	1.02
योग	2.02
	+ 4.06
	6.08
7. *इंजिनियरिंग महाविद्यालय*	
क्षमता	वास्तविक नामांकन
पुरुष	989
महिला	—
योग	989
8. *पोलिटेकनिक महाविद्यालय*	
प्रवेश क्षमता	
पुरुष	1515
महिला	180
योग	1695

9.	*औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान*	
	पुरुष	10772
	महिला	228
	योग	11000
10.	*प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय*	
	पुरुष	1996
	महिला	1623
	योग	3619
11	*माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय*	
	प्रवेश क्षमता	
	पुरुष	3893
	महिला	2490
	योग	6383
12.	*साक्षरता प्रतिशत (1991 की जनगणनानुसार)*	
	सामान्य (7 वर्ष तथा ऊपर)	
	पुरुष	55.07
	महिला	20.84
	योग	38.81
13.	*ग्रामीण क्षेत्र*	
	पुरुष	29.65
	महिला	5.46
	योग	17.99
	शहरी क्षेत्र	
	पुरुष	60.55
	महिला	34.29
	योग	46.35
	अनुसूचित जनजाति	
	पुरुष	24.10
	महिला	2.69
	योग	14.04
	ग्रामीण क्षेत्र	
	पुरुष	20.51

महिला	1.81
योग	11.26
शहरी क्षेत्र	
पुरुष	41.93
महिला	9.71
योग	26.75
अनुसूचित जाति जनजाति	
पुरुष	17.88
महिला	0.93
योग	9.61
14. भौगोलिक स्थिति (वास्तविक संख्या)	
जिले	30
उपखण्ड	88
तहसील	203
पंचायत समिति	237
नगरपालिका	192
ग्राम पंचायत	7553
कुल ग्राम	37124
कुल नगर एवं गाँव – 201	
15 जनसंख्या (जनगणना 1991 के अनुसार)	
पुरुष	2.29 करोड़
महिला	2.09 करोड़
योग	4.38 करोड़
अनुसूचित जाति	58.38 लाख व
अनुसूचित जनजाति	41.83 लाख

क्षेत्रफल – 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर

महाविद्यालय शिक्षा : संक्षिप्त सांख्यिकी विवरण वर्ष 1991-92

राज्य में उच्च शिक्षा की संस्थाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :–

1. विश्वविद्यालय की संख्या	6
2. डीम्ड विश्वविद्यालय	4
3. महाविद्यालय	

क्षेत्र	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल		विशेष विवरण
(अ)	सरकारी	37	32		6 स्वायत्तशासी
					6 जनजाति उपयोजनाक्षेत्र
					7 महिला कालेज
(ब)	निजी				
	(1) सहायता प्राप्त	23	27	50	12 महिला महाविद्यालय
	(2) असहायता प्राप्त	44	3	47	28 महिला महाविद्यालय
	कुल	104	62	166	

सत्र 1991-92 की नामांकन स्थिति

	छात्र	छात्रा	योग
(1) स्वायत्तशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय	12518	1831	14349
(2) राज स्नातकोत्तर महाविद्यालय	16908	3446	20354
(3) राज. स्नातक महाविद्यालय	8257	5910	14167
(4) सहायता प्राप्त पी. जी. महाविद्यालय	16387	2688	19075
(5) सहायता प्राप्त स्नातक महाविद्यालय	6541	4698	11239
(6) असहायता प्राप्त पी. जी. महाविद्यालय	665	623	1288
(7) असहायता प्राप्त स्नातक महाविद्यालय	2308	2563	4871
कुल	63584	21759	85343

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-7272
Date 16.11.92

NIEPA DC
D07272